

गैस सिलेण्डर की वास्तविक मूल्य 995 रुपये, होम डिलीवरी 1030 रुपए

गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही। जिला खाद्य अधिकारी द्वारा गैस सिलेण्डर के सभी उपभोक्ता को सूचित किया गया है कि गैस सिलेण्डर का होम डिलीवरी सेवा शुल्क के साथ कुल मूल्य 1030 रुपए है, जिसमें वितरक द्वारा घर पहुंच सेवा दी जाती है। यदि उपभोक्ता स्वयं गैस एजेंसी से गैस सिलेण्डर लेने जाते है तो वास्तविक मूल्य 995 रुपए ही देय होगा। यदि उपभोक्ता ऑनलाईन राशि पूर्व से 1030 रुपए जमा कर चुका है, तो वे 35 रुपए छूट (रिबेट) की राशि गैस सिलेण्डर लेने जाने पर वितरक एंजेंसी से प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर प्राप्त डीएससी क्रमांक को गैस सिलेण्डर रिफिल डिलेवरी के उपरांत ही वितरक को राशि प्रदाय करें। शिकायत की स्थिति में इण्डेन गैस कम्पनी के सेल्स ऑफिसर श्री राहुल देवांगन के मोबाईल नम्बर 7828842315 पर शिकायत दर्ज करा सकते है।

शिक्षकों की समस्याओं व स्कूलों की सुविधाएं को लेकर कलेक्टर गंभीर

कांकेर। शिक्षकों की समस्याओं और स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं को कलेक्टर कुंदन कुमार ने गंभीरता से लिया है। शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण एवं स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी और अपर कलेक्टर कांकेर को खण्ड शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा करने तथा उसका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है।जिला शिक्षा अधिकारी को आज ही सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेकर शिक्षकों की समस्याओं और स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करने तथा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया है।

सीएम कार्यक्रम में पहुंचे इसलिए नींबू काटकर बारिश को रोक दिया : सांसद भोजराज नाग

बालोद। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले कांकेर सांसद भोजराज नाग का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा, जिसमें वह महादेव से प्रार्थना करके नींबू काट कर बारिश को रोक देने की बात कह रहे।दरअसल मंगलवार को बालोद जिले के डौंडीलोहारा के मिनी स्टेडियम में मातृ शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सांसद भोजराज नाग ने मंच से कहा कि खराब मौसम में भी मुख्यमंत्री यहां आने के लिए जब 12 बजे रात को प्रोटोकॉल जारी किए तब मैंने बूढ़ादेव, महादेव से प्रार्थना करके नींबू काट कर बारिश को रोक रूकवा दिया, ताकि सीएम बालोद आ सकें।



ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर माओवादियों का बड़ा डंप बरामद, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक जब्त



जगदलपुर। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर फोर्स (घड़ुस्न) ने बुधवार तड़के ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा से लगे वन क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाकर माओवादियों का एक बड़ा डंप बरामद किया।

डंप से हथियार, आईईडी, क्लेमोर माइन और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक, आत्मसमर्पण कर चुके

माओवादियों से पूछताछ के आधार पर घड़ुस्न की टीम ने मथिली थाना क्षेत्र के चेरकोटला, किर्मिनी, कोटवापादर और कडाभाटा के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया।

यह इलाका छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा थाना और सुकमा जिले के पुष्पपाल थाना क्षेत्र से सटा हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने तीन देसी बंदूकें, 5 किलो, 3 किलो और 2 किलो वजन के कई आईईडी, दो क्लेमोर माइन, कोडेक्स वायर,

माओवादी बैनर समेत बड़ी मात्रा में अन्य सामान बरामद किया है। बरामद सामग्री को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लेकर आगे की जांच की जा रही है। बता दें कि ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा का यह इलाका लंबे समय से माओवादी गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील रहा है। ऐसे में डंप की बरामदगी को सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इलाके में सर्च ऑपरेशन और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।

आखिरी सामान्य सभा में गरमाया सदन, 15 प्रस्ताव पारित

भिलाई नगर निगम की आखिरी सामान्य सभा में 15 विषयों पर चर्चा के बाद सभी एजेंडे पारित किए गए

दुर्ग। भिलाई नगर निगम की इस कार्यकाल की आखिरी सामान्य सभा मंगलवार को आयोजित हुई।सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर हल्की नोक-झोंक देखने को मिली। सामान्य सभा में कुल 15 विषयों पर चर्चा के बाद सभी एजेंडे पारित कर दिए गए।

सभा में केनाल रोड का नाम भगवान परशुराम मार्ग करने, दो चौकों का नाम परशुराम चौक और मां परमेश्वरी चौक रखने, तिराहों-चौराहों के नामकरण, नेहरू नगर पूर्व स्थित खेल मैदान का नाम शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे खेल मैदान रखने जैसे प्रस्ताव शामिल रहे। इसके अलावा नए निगम कार्यालय भवन, जवाहर मार्केट के उन्नयन, स्ट्रीट लाइट के संचालन-संधारण, गोकुल धाम कुरुद के भूखंडों की राशि, लीज भूमि के प्रयोजन परिवर्तन और हस्तांतरण शुल्क से जुड़े प्रस्ताव भी पारित किए गए। प्रियदर्शनी परिसर में 1000 सीटर ऑडिटोरियम और सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और प्राकृतिक फुटबॉल मैदान निर्माण का प्रस्ताव भी सभा में रखा गया।

वहीं विपक्ष के नेता भोजराज सिन्हा ने आरोप लगाया कि कई एजेंडे निगम सरकार अपने हितों के लिए लाई



थी। उन्होंने शहर में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शिक्षा कर और यूजर चार्ज के नाम पर जनता से अवैध वसूली का आरोप लगाया। उनका कहना था कि भिलाई में निगम का एक भी स्कूल नहीं है, फिर भी शिक्षा कर लिया जा रहा है। उन्होंने

महापौर और सभापति पर चर्चा रोकने का भी आरोप लगाया।

वहीं महापौर नीरज पाल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी 15 विषयों पर सदन में पर्याप्त चर्चा हुई और पक्ष-विपक्ष के पार्षदों को बोलने का पूरा अवसर दिया गया।

उन्होंने कहा कि जमीन आवंटन से जुड़े नियमों का उल्लंघन होने की शिकायत आयुक्त से की गई है और राज्य सरकार से भी मामले में संज्ञान लेने की मांग की गई है।आखिरी सामान्य सभा में विकास कार्यों के साथ-साथ आरोप-प्रत्यारोप ने भी जमकर सुर्खियां बटोरीं।

जिपं भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन का 2 सितंबर तक

जीपीएम। कार्यालय जिला पंचायत द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत 20 अगस्त को आयोजित दस्तावेज परीक्षण में कुल 4 पदों के विरुद्ध 20 अभ्यर्थियों ने दस्तावेज परीक्षण कराया। इनमें विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक अनारक्षित के 1 पद के लिए 7, विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक अनुसूचित जनजाति के पद के लिए 5, क्षेत्रीय समन्वयक अनुसूचित जनजाति के 1 पद के लिए 4 तथा लेखापाल अनारक्षित के 1 पद के लिए 4 अभ्यर्थी शामिल हैं। इसके अलावा 8 अभ्यर्थियों ने ई-मेल के माध्यम से सूचना दी कि 20 अगस्त को अन्य जिले में विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक की परीक्षा होने के कारण वे दस्तावेज परीक्षण में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने दस्तावेज सत्यापन के लिए अन्य तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया था। चयन समिति के निर्णय एवं विज्ञापन के नियम के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों में वरीयता क्रम के आधार पर एक पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के आगामी चरण कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाना है।

महासमुंद जिले का गौरवपथ गड्डों से भरा करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़क की तय सीमा समाप्त

महासमुंद। प्रदेशभर में कई जगह बदहाल सड़कों ने बारिश में और परेशानी बढ़ा दी है। महासमुंद में भी खराब सड़क की वजह से आम जनता के साथ सावन महीने में पैदल चलने वाले कांवड़िए और भी परेशान हो रहे हैं। गौरव पथ, बीटीआई रोड और कलेक्टोरेट पहुंच मार्ग में जगह-जगह गड्डों से गाड़ी के साथ पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। करीब 2।3 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए शासन ने लगभग 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। निर्माण को जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गई और विभाग ने मई 2025 में मेसर्स किरण बिल्डकान, बेमेतरा को कार्यदेश जारी किया। निर्माण कार्य फरवरी 2026 तक पूरा होना था, लेकिन तय समय-सीमा गुजर जाने के बाद भी काम अधूरा है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 50 प्रतिशत ही काम पूरा हो पाया है। कलेक्टोरेट से बरोड़ा चौक तक लगभग डेढ़ किलोमीटर सड़क पर जगह-



जगह गड्डे हैं। वाहन भी गड्डों के बीच हिचकोले खाते हुए गुजर रहे हैं। इसी रास्ते से जिले के आला अधिकारियों से लेकर आम नागरिकों की रोजाना आवाजाही होती है।

इसके बावजूद सड़क का समय पर निर्माण पूरा नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। सबसे ज्यादा परेशानी इस सावन में उन कांवड़ियों को हो रही है, जो बम्हनी से जल लेकर करीब 45 किलोमीटर दूर सिरपुर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने पैदल जाते हैं। कांवड़ियों का कहना है कि खराब सड़क और बिखरे पत्थरों के कारण नंगे पैर चलना बेहद मुश्किल हो गया है। गड्डों और उबड़-खाबड़ रास्ते की वजह

से पैरों में छाले पड़ रहे हैं और चोट लगने का भी खतरा बना हुआ है। सड़क की बदहाली को लेकर जब जिम्मेदार विभागों से सवाल किया गया तो लोक निर्माण विभाग और बिजली विभाग के अधिकारी अपने-अपने तर्क देते नजर आए। जहां बिजली विभाग ने कहा कि इसकी निर्माण एजेंसी ऋद्धि ही है। उनके अपने एजेंसी से ही टेंडर हुआ है। हमारा काम सिर्फ परमिट देना है। अपने एजेंसी से ही वे निर्माण करा रहे हैं। वहीं, ऋद्धि के स्तर ने कहा कि पैच निर्माण का कार्य नियमित रूप से कराया जा रहा है। बारिश के कारण अभी काम नहीं हुआ है, दिसंबर 2026 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

नहरनाका में आधी रात हुआ हंगामा, बीच सड़क पर बैठे नेताजी

सड़क के बीचों बीच बैठे नेताजी को हटाने के लिए पुलिस समझाती रही, लेकिन नेताजी हटने को तैयार नहीं थे



धमतरी। बिना राजस्व चुकाए रेत का परिवहन किया जाना शहर में कोई नई बात नहीं है। महानदी का सीना चीरकर अवैध तरीके से रेत खनन की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। राजस्व विभाग और माइनिंग डिपार्टमेंट लगातार कार्रवाई भी कर रही हैं। बावजूद इसके अवैध रेत का खनन और परिवहन करने वाले कानून व्यवस्था के लिए लगातार चुनौती बने हुए हैं। मंगलवार दे रात कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नहर नाका चौक पर रेत से लदी 8 गाड़ियों को रोक दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब ड्राइवर से रेत का पिट पास मांग गया, तब गाड़ी चालकों ने पिट पास नहीं होने की बात उनको बताई। कांग्रेस का कहना है कि गलत तरीके से रेत का खनन और परिवहन दोनों शहर में लगातार चल रहा है। लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि 40 से 32 टन की गाड़ियां यहां से गुजरती हैं

जिससे सड़कें खराब हो रही हैं। यहां बिना रायल्टी दिए यहां से कई गाड़ियां रोज गुजर रही हैं। हमने अधिकारियों को फोन लगाया लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। यहां से भिलाई दुर्ग और ओडिशा तक रास्ता जाता है। सड़क की हालत क्या है सब जानते हैं-गौतम वाधवाकर, कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रेत के अवैध खनन और परिवहन को लेकर सड़क पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन की वजह से रेत लदे ट्रकों और वाहनों की दोनों ओर लंबी-लंबी कतारें लग गईं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने रेत से लदे वाहनों को बिना पिट पास के जाने की खबर अधिकारियों को देनी चाही, तो अधिकारी ने उनका फोन तक नहीं उठाया। कांग्रेस का कहना है कि करीब 1 घंटे तक वो फोन लगाते रहे लेकिन अधिकारी ने उनका फोन नहीं उठाया।

राखी का धागा रहा पुकार-इसमें शामिल विष्णु भैया का प्यार

एमसीबी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मातृशक्ति सम्मान समारोह-2026 में महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 67.28 लाख बहनों के खातों में 7631 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की। रक्षाबंधन से पहले मिली इस राशि से प्रदेश की महिलाओं में खुशी का माहौल है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम नागपुर निवासी पदमनी वैष्णव भी इस सीगत से बेहद खुश हैं। पदमनी वैष्णव ने बताया कि महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त की राशि उनके खाते में पहुंचने से रक्षाबंधन का त्योहार और भी खुशी से मनाने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व है। त्योहार से पहले आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें राखी, मिठाई और फल खरीदने में सुविधा होगी। वे प्राप्त राशि का उपयोग रक्षाबंधन की तैयारियों में करेंगी और अपने परिवार के साथ खुशी से त्योहार मनाएंगी। उन्होंने कहा कि समय से पहले इस राशि का मिलना हम महिलाओं के लिए बेहद खुशी की बात है।

तेंदुआ शावकों को मां से मिलाया, मिशन रीयूनाइट सफल

बस्तर। छत्तीसगढ़ का वनांचल इलाका बस्तर संभाग अपने प्राकृतिक खूबसूरती और जंगलों के लिए जाना जाता है। यहां के जंगल से एक खुशखबरी सामने आई है। वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से तेंदुए के दो बिछड़े शावकों को मिलाने का काम हुआ है। बस्तर वन विभाग ने इसे मिशन रीयूनाइट का नाम दिया और 48 घंटे के अंदर तेंदुए के दो शावकों को उनकी मां से मिलाने का काम किया गया। यह पूरी घटना बस्तर के चित्रकोट जंगल की है। बस्तर वन विभाग को 22 अगस्त को सूचना मिली की ग्रामीण बच्चों ने तेंदुए के एक छोटे शावक को अपने पास रखा है। इस सूचना पर वन विभाग की टीम एक्टिव हुई। बस्तर वन मंडल अधिकारी दीपेश कपिल की अगुवाई में तत्काल वन विभाग के सदस्य चित्रकोट रेंज के जंगल में पहुंचे। 22 अगस्त की रात 11।20 बजे शावक को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया। उसके बाद उसे सुबह 4 बजे जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर रखा। जिससे उसकी मां उसे ले जा सके। इसके बाद वन विभाग को तेंदुए के दूसरे शावक के बारे में पता चला।

जिपं भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन का 2 सितंबर तक

जीपीएम। कार्यालय जिला पंचायत द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत 20 अगस्त को आयोजित दस्तावेज परीक्षण में कुल 4 पदों के विरुद्ध 20 अभ्यर्थियों ने दस्तावेज परीक्षण कराया। इनमें विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक अनारक्षित के 1 पद के लिए 7, विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक अनुसूचित जनजाति के पद के लिए 5, क्षेत्रीय समन्वयक अनुसूचित जनजाति के 1 पद के लिए 4 तथा लेखापाल अनारक्षित के 1 पद के लिए 4 अभ्यर्थी शामिल हैं। इसके अलावा 8 अभ्यर्थियों ने ई-मेल के माध्यम से सूचना दी कि 20 अगस्त को अन्य जिले में विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक की परीक्षा होने के कारण वे दस्तावेज परीक्षण में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने दस्तावेज सत्यापन के लिए अन्य तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया था। चयन समिति के निर्णय एवं विज्ञापन के नियम के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों में वरीयता क्रम के आधार पर एक पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के आगामी चरण कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाना है।

मनेन्द्रगढ़ में भरभराकर गिरा तीन मंजिला मकान

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। जिले में लगातार हो रही तेज बारिश ने मनेन्द्रगढ़ शहर में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वार्ड नंबर 9 में बुधवार को बारिश के बीच एक तीन मंजिला मकान अचानक भरभराकर जमींदोज हो गया। मकान गिरते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि हादसे के वक आसपास मौजूद लोग सुरक्षित बच गए और किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण मकान की स्थिति कमजोर हो गई थी। अचानक पूरा भवन भरभराकर सड़क की ओर गिर पड़ा। मकान के मलबे की चपेट में सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे और तार भी आ गए। खंभे टूटकर सड़क पर गिरने से इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। वहीं, मलबा और बिजली के तार सड़क पर फैल जाने से यातायात भी प्रभावित हुआ। घटना की सूचना मिलते ही नगरपालिका और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से जानकारी ली।

बाढ़े में बतख को निगल रहा था 9 फीट का अजगर

कोरबा। कोरबा जिले के भूलसीडीह गांव में बुधवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक फार्म हाउस में पाले गए बतख को अजगर ने अपना शिकार बना लिया। बाढ़े के अंदर अजगर को बतख को निगलते देख घर वालों के होश उड़ गए। जानकारी के अनुसार, हीरा उरांव ने अपने फार्म हाउस में तीन बतख पाल रखे हैं। रोज की तरह सुबह वह बतखों को दाना देने के लिए आवाज लगा रहे थे। दो बतख तो बाहर आ गए, लेकिन तीसरा बतख बाहर नहीं आया। अनहोनी की आशंका पर जब हीरा उरांव ने बाढ़े के अंदर झांक कर देखा तो नजारा देखकर वे दंग रह गए। एक विशाल अजगर ने बतख को जकड़ रखा था और उसे निगल रहा था। घटना से घबराए हीरा उरांव ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग से जुड़े वाइल्डलाइफ रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को दी। सूचना मिलते ही सारथी ने तुरंत अपनी टीम के सदस्य राजू बर्मन और राकेश मानिकपुरी को मौके के लिए रवाना किया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच जारी रखने का अधिकार नहीं

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द की वार्जरीट

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संबंध में एक महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच तभी जारी रखी जा सकती है, जब संबंधित सेवा नियमों में इसके लिए स्पष्ट और सक्षम प्रावधान मौजूद हो। ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में विभागीय कार्यवाही जारी रखने का अधिकार नियोक्ता को प्राप्त नहीं है। न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल की एकलपीठ ने यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के सेवानिवृत्त डिविजनल मैनेजर नंदकिशोर अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत याचिका पर पारित किया। याचिकाकर्ता को 24 जुलाई 2019 को विभागीय आरोप-पत्र जारी किया गया था। इसके मात्र सात दिन बाद, 31 जुलाई 2019 को वे रिटायर हो



गए। रिटायरमेंट के बाद भी विभागीय कार्यवाही जारी रखने के प्रयास को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता को ओर से कोर्ट के समक्ष तर्क दिया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कर्मचारी सेवा विनियम, 1984 में सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच जारी रखने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में निगम के पास कार्यवाही जारी रखने का वैधानिक अधिकार अथवा अधिकारिता नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि

नियोक्ता विभागीय कार्यवाही केवल उन्हीं परिस्थितियों में शुरू अथवा जारी रख सकता है, जिनकी अनुमति संबंधित सेवा नियमों में दी गई हो।

सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने के लिए महज प्रशासनिक शक्ति रखने नहीं है; इसके लिए स्पष्ट वैधानिक आधार आवश्यक है। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि निगम द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया, जो

याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच जारी रखने का अधिकार प्रदान करता हो।

केवल कर्मचारी की परिभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया था। हाईकोर्ट ने माना कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कर्मचारी सेवा विनियम, 1984 में सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच जारी रखने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण निगम के पास ऐसी कार्यवाही जारी रखने की अधिकारिता नहीं थी। इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2019 को जारी विभागीय आरोप-पत्र को निरस्त कर दिया और याचिका को स्वीकार कर लिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच की निरंतरता सेवा नियमों में उपलब्ध स्पष्ट वैधानिक प्रावधान पर निर्भर करती है; उसके अभाव में ऐसी कार्यवाही स्वतः आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।

आत्मानंद स्कूल के 400 छात्रों का रात 12 बजे तक चक्काजाम

प्राचार्य को हटाया, 4 नए शिक्षकों की पदस्थापना

दुर्ग। धमधा क्षेत्र के पेंड्रावन स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में 400 छात्रों के लिए महज 3 शिक्षकों की व्यवस्था से नाराज विद्यार्थियों ने मंगलवार को खैरागढ़-धमधा मुख्य मार्ग पर करीब 12 घंटे तक चक्काजाम कर दिया। दिन को 12 बजे से बैठे छात्र रात 12 बजे तक डे रहे। आखिरकार शिक्षा विभाग को छात्रों की मांगों के आगे झुकना पड़ा। 400 छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल में केवल 3 शिक्षक और एक प्राचार्य पदस्थ थे।

शिक्षकों की कमी के चलते खासकर आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी और



छात्रों का सिलेबस भी अधूरा था। इसी समस्या को लेकर 9वीं से 12 वीं तक के करीब 400 छात्र मंगलवार दोपहर खैरागढ़-धमधा मुख्य मार्ग पर बैठ गए और चक्काजाम कर दिया। एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन छात्र ठोस समाधान की मांग पर अड़े रहे। छात्रों का कहना था कि इससे पहले 21 अगस्त को भी उन्होंने शिक्षक की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। अधिकारियों ने जल्द व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिया था,

लेकिन 25 अगस्त तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने पर छात्रों का सब्र जवाब दे गया। करीब 12 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के बाद देर रात स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने मामले का संज्ञान लिया।

मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और छात्रों से फोन पर बातचीत कर उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। मंत्री के निर्देश के बाद पेंड्रावन स्कूल के प्राचार्य आरके चंदेल को तत्काल हटा दिया गया और नए प्राचार्य की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही 4 नए शिक्षकों की पदस्थापना कर दी गई है। अब स्कूल में शिक्षकों की संख्या 7 हो गई है।

संक्षिप्त समाचार

जाति जनगणना पर मोदी को पत्र लिखे जाने पर राहुल से संतोष पांडेय का सवाल

रायपुर। जातिगत जनगणना को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे जाने पर सांसद संतोष पांडे ने बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी बताएं कि वे किस जाति से हैं? क्या राहुल गांधी पारसी हैं? देश को बताना चाहिए आखिर राहुल और प्रियंका किस जाति के हैं? वहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासी कांग्रेस की बैठक को लेकर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों का शोषण करती है। आदिवासियों को अपमानित, जेल भेजने का काम करती है। भूपेश बघेल के कार्यकाल में क्या स्थिति थी, सब जानते हैं। बीजेपी के मेरथन बैठक पर सांसद संतोष पांडे का बयान हम अपने शस्त्र को मांजते रहते हैं। शांति काल में भी बीजेपी युद्ध के लिए तैयार रहती है। अलग-अलग कार्यक्रमों की समीक्षा हो रही है। आने वाले दिनों के लिए कार्यक्रम को रणनीति तय हो रही है।

सीजीपीएससी घोटाला: जेल में बंद टामन सोनवानी की बिगड़ी तबीयत

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाले में जेल में बंद पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट, अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल, तबीयत में सुधार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, पूर्व पीएससी चेयरमैन व रिटायर्ड आईएसएस टामन सिंह सोनवानी की 18 अगस्त को अचानक तबीयत बिगाड़ी थी। ब्रेडीकार्डिया की स्थिति बनने पर आनन-फानन में एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट, अंबेडकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रखने के बाद हार्ट अटैक की आशंका के चलते पेपमेकर लगाया है। अब स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी पेपर लीक और धनशोधन के आरोपों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्त में हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग के नए संचालक महदेव क्षीरसागर ने ग्रहण किया पदभार

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नए संचालक भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने इंद्रावती भवन में अपना पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे कांकेर जिले के कलेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे। राज्य शहरी विकास अधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अशवाल, नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य, मुख्य अभियंता श्री राजेश शर्मा और अपर संचालक (वित्त) युनुस खान सहित नगरीय प्रशासन विभाग तथा सूडा के अधिकारी भी उनके पदभार ग्रहण करने के दौरान मौजूद थे। नगरीय प्रशासन विभाग के नए संचालक क्षीरसागर ने पदभार ग्रहण करने के बाद विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा से सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने अपने कार्यालय में विभागीय अधिकारियों का परिचय प्राप्त कर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और राज्य शहरी विकास अधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने कार्यों की तेज प्रगति, नगरीय निकायों के समग्र विकास तथा शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया।

दुर्ग-रायगढ़-दुर्ग के बीच कल से 3-3 फेरों के लिए वलेंगो रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन

रायपुर/बिलासपुर। भाई-बहनों के स्नेह और विश्वास के पावन पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा दुर्ग-रायगढ़-दुर्ग के मध्य रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इस स्पेशल ट्रेन के परिचालन से रक्षाबंधन पर्व पर अपने परिवार एवं प्रियजनों से मिलने जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध होगी। गाड़ी संख्या 08834 दुर्ग-रायगढ़ रक्षाबंधन स्पेशल 27, 28 एवं 29 अगस्त 2026 को दुर्ग से रायगढ़ के लिए चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 08833 रायगढ़-दुर्ग रक्षाबंधन स्पेशल 27, 28 एवं 29 अगस्त 2026 को रायगढ़ से दुर्ग के लिए चलेगी। इस रक्षा बंधन स्पेशल ट्रेन का दुर्ग-रायगढ़-दुर्ग के सभी मध्यवर्ती स्टेशनों में ठहराव की सुविधा प्रदान की गई है जिससे सभी स्टेशनों के यात्रियों को सुगम यात्रा सुविधा का लाभ मिलेगा। गाड़ी संख्या 08834 दुर्ग-रायगढ़ रक्षाबंधन स्पेशल 27, 28 एवं 29 अगस्त 2026 को दुर्ग से 10.30 बजे रवाना होगी तथा मार्ग के अन्य सभी मध्यवर्ती स्टेशनों में ठहरते हुये बिलासपुर 14.45 बजे, अकलतरा 15.27 बजे , जांजगीर-नैला 15.44 बजे , चांपा 15.55 बजे, बाझाढ़गर 16.13 बजे, सक्ती 16.59 बजे , खरसिया 17.16 बजे होते हुये रायगढ़ 19.03 बजे पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 08833 रायगढ़-दुर्ग रक्षाबंधन स्पेशल दिनांक 27, 28 एवं 29 अगस्त 2026 को रायगढ़ से 19.40 बजे रवाना होगी तथा मार्ग के अन्य सभी मध्यवर्ती स्टेशनों में ठहरते हुये खरसिया 20.13 बजे, चांपा 21.00 बजे, अकलतरा 21.25 बजे, बिलासपुर 22.20 बजे होते हुये दूसरे दिन दुर्ग 02.00 बजे पहुंचेगी।

कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा : सीएम साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आदिवासी कांग्रेस की बैठक को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। अगर वास्तव में किसी ने जनजाति समाज की चिंता की है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। मुख्यमंत्री साय ने आदिवासियों के हित में भाजपा सरकार द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अनुसूचित जनजाति समाज के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया था। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू आज देश की राष्ट्रपति हैं। इस उपलब्धि ने पूरे जनजातीय समाज को गौरव और सम्मान दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की लगभग सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आदिवासी समाज को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की



विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना शुरू की है। इसके तहत उनके गांवों तक सड़कें पहुंचाई जा रही है। राशन कार्ड समेत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन जनजातीय समाज अब उसे पहचान चुका है और जनता उसके मुगालते में आने वाली नहीं है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में फिर से पेपर लीक की घटना को लेकर मुख्यमंत्री साय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों को

किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

बीजेपी की जारी बैठकों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी में बैठकें लगातार

चलती रहती हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलरामपुर-जशपुर दौरे के लिए रवाना हुए। अपने दौरे को लेकर उन्होंने बताया कि वे दो दिन के जशपुर प्रवास पर रहेंगे और अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पंडरीपानी में स्टेट बैंक की नई शाखा का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना का भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण किया जाएगा। दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया जाएगा।

सांसद भोजराज नाग के बयान पर बैज ने कसा तंज, कहा- तो नींबू काटकर महंगाई रोक दें! पेट्रोल-शक्कर की कीमतें कम करवा दें!

रायपुर। कांग्रेस सांसद भोजराज नाग के वायरल हो रहे वीडियो में वह नींबू काटकर बारिश रोकने की बात कह रहे हैं। सांसद नाग के बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए बयान पर कसा तंज कहा कि अगर नींबू काटने से बारिश रुक जाती है, तो



नींबू काट कर महंगाई रोक दें! पेट्रोल-शक्कर की कीमतें कम करवा दें! बिजली बिल कम करवा दें!

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में भाजपा का दो दिसवीय समन्वय बैठक पर कहा कि भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मंत्रियों का इस्तीफा लेकर रख लिया गया है। सभी का परफॉर्मेंस जोरो है। सुनने में आया है कि संगठन ने कुछ मंत्रियों को कड़ी फटकार लगाई है। सभी मंत्री

कमीशनखोरी में लगे हुए हैं। कुछ मंत्री तो रोते हुए बैठक से बाहर आए हैं। मंत्रिमंडल में अब बदलाव की नहीं, इस को सरकार बदलने की जरूरत है।

वहीं स्कूली छात्रों के आंदोलन पर बैज ने कहा कि शिक्षा मंत्री कठपुतली की तरह विभाग को चला रहे हैं। स्कूलों में किताबें नहीं हैं, टीचर नहीं हैं, भवन नहीं हैं। स्कूलों में पानी भरा है। बदहाल शिक्षा व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? जेन अल्फा ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया।

सड़कों पर जेन-अल्फा: बच्चों को उकसा कर कांग्रेस करवा रही प्रदर्शन- शिक्षा मंत्री

रायपुर। दिल्ली के जंतर-मंतर में नीट परीक्षा लीक को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव दिख रहा है। जेन-जी के बाद, अखंडी शिक्षा, टीचरों की कमी जैसे मुद्दे पर पर अब जेन-अल्फा सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेशभर में स्कूली बच्चों के प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों को उकसा कर कांग्रेस प्रदर्शन करवा रही है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने अलग-अलग जिलों से सामने आ रहे स्कूली छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के कारण यह प्रदर्शन हो रहे हैं। बच्चों को आगे कर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री गजेंद्र स्कूली छात्रों के प्रदर्शन को

कांग्रेस जनित प्रदर्शन करार दिया और कहा कि सरकार प्रदेशभर में 8 हजार शौचालय का निर्माण करने वाली है। कांग्रेस श्रेय की राजनीति कर रही है। बच्चों को उकसा कर उनसे प्रदर्शन करवाया जा रहा है। युवा कांग्रेस चुनाव पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस मामले में मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस में लड़ाई नई बात नहीं है। भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव के बीच लड़ाई शुरू से है। इस बार भी नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हो रही मेरथान बैठकों को लेकर मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा दिया कि बीजेपी में लगातार काम काज को लेकर बैठक होती है। लगातार प्रभार जिलों में भी बैठक करते हैं। समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करते हैं।



राखी के पूर्व बहनों को सौगात, 20076 करोड़ रुपए बहनों के खातों में किए गए हस्तांतरित: शताब्दी पाण्डे

प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार महिला हितैषी सरकार

रायपुर। माह सितम्बर की 31वीं किश्त की राशि अंतरित की गई है, यह राखी त्यौहार को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रदेश सरकार द्वारा राखी के पूर्व बहनों को यह भेंट दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती शताब्दी पाण्डे ने कहा है कि कल 25 अगस्त को जिला बालोद में महतारी वंदन सम्मान समारोह के आयोजन के दौरान 31वीं किश्त का भुगतान किया गया। माह सितम्बर 2026 की 31वीं किश्त के भुगतान ई-केवायसी करा चुकीं कुल 67,28,918 हितग्राहियों को कुल राशि 631,38,37,700 रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया। इनमें नियद नेल्लानार के हितग्राहियों के 6,897 हितग्राही भी शामिल हैं, जिन्हें 11वीं किश्त का भुगतान हुआ है। इस प्रकार अब तक कुल 20076 करोड़ रुपये का भुगतान बहनों को किया गया।



श्रीमती पाण्डे बताया कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार समाज के हर वर्ग तक महतारी वन्दन योजना का लाभ पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री श्री साय ने महिलाओं को महतारी वन्दन योजना के

माध्यम से राशि उपलब्ध कराने का कार्य शुरू किया है। भाजपा सरकार प्रदेश की हर माता और बहन के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा से समर्पित है।

महतारी वन्दन योजना की 31वीं किश्त जारी होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्रीमती पाण्डे ने इसे प्रदेश सरकार का नारी सशक्तीकरण की दिशा में बढ़ता कदम बताया और कहा कि भाजपा सरकार को कहती है, वह करके दिखाती है। श्रीमती पाण्डे ने बताया कि 1 मार्च 2024 से लागू हुई महतारी वन्दन योजना ने राज्य की माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उनके सामाजिक सशक्तीकरण, सुकन्या समृद्धि योजना, स्वावलंबन, कुपोषण एवं एनीमिया निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महतारी वन्दन योजना में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

विष्णु भैया का प्यार महतारी वंदन योजना से मिला उपहार

रायपुर। एससीबी जिले की पदमनी ने रक्षाबंधन के पहले महतारी वंदन योजना की एक हजार रुपये मिलने पर मुख्यमंत्री मंत्री विष्णु भैया के प्रति आभार जताया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मातृशक्ति सम्मान समारोह-2026 में महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 67.28 लाख बहनों के खातों में 631 करोड़ रूपए से अधिक की राशि अंतरित की। रक्षाबंधन से पहले मिली इस राशि से प्रदेश की महिलाओं में खुशी का माहौल है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम नागपुर निवासी पदमनी वैष्णव भी इस सौगात से बेहद खुश हैं। पदमनी वैष्णव ने बताया कि महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त की राशि उनके खाते में पहुंचने से रक्षाबंधन का त्योहार और भी खुशी से मनाने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व है। त्योहार से पहले आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें राखी, मिठाई खरीदने में सुविधा होगी।

भाजपा सरकार ने आदिवासियों को दिया वास्तविक नेतृत्व और अधिकार: मरकाम

रायपुर। छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परम्परा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जनजाति विरोधी राजनीतिक चरित्र पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जबकि भाजपा ने आदिवासियों को वास्तविक सशक्तीकरण, सम्मान और शासन में सर्वोच्च नेतृत्व प्रदान किया है। आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की संवेदनशील सरकार में आदिवासी समाज का गौरव पूरे देश में बढ़ा है। मरकाम ने शीर्ष नेतृत्व और प्रतिनिधित्व की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में स्वयं आदिवासी समाज के संपूत कमान सम्भाल रहे हैं। साथ ही मंत्रिमण्डल में दो सशक्त कैबिनेट मंत्रियों सहित विभिन्न निगमों, मंडलों और आयोगों में अजजा वर्ग को भरपूर प्रतिनिधित्व देकर भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व है। त्योहार से पहले आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें राखी, मिठाई खरीदने में सुविधा होगी।



जुटे हैं। इन प्राधिकरणों के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तेजी से विकास कार्य स्वीकृत हो रहे हैं। आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा को योजनाओं का उल्लेख कर मरकाम ने कहा कि तेंदूपता संग्रहण दर में ऐतिहासिक वृद्धि कर संग्रहकों को सीधा आर्थिक लाभ पहुँचाया जा रहा है। लघु वनांचलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों, उन्नत स्वास्थ्य शिविरों और स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं को संस्थागत संरक्षण देकर अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएँ पहुँचाई जा रही हैं। मरकाम ने कहा कि कांग्रेस के पास आदिवासियों के उत्थान के नाम पर केवल खोखले वादे थे, जबकि भाजपा सरकार धरातल पर ठोस योजनाएँ लागू कर अजजा वर्ग का सर्वतोमुखी विकास सुनिश्चित कर रही है। आदिवासी समाज अब कांग्रेस के दोहरे चरित्र को भली-भाँति समझ चुका है और पूरी मजबूती के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है।

आदिवासी कांग्रेस की बैठक में विक्रांत भूरिया के शामिल होने पर अजय चंद्राकर का तंज, कहा- मप्र की राजनीति में बनाएं अपनी पहचान, छग में बहुत हैं आदिवासी नेता

रायपुर। आदिवासी कांग्रेस की बुधवार को होने वाली बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया शामिल होने पर वरिष्ठ भाजपा नेता और विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि विक्रांत भूरिया को मध्यप्रदेश की राजनीति में पहचान बनानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में बहुत स्थापित आदिवासी नेता हैं। प्रदेश में बघेल का नेतृत्व भी बहुत है। उनका आना 'मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है' जैसा है। वहीं जल-जंगल जमीन को खतरा बताए जाने पर अजय चंद्राकर ने कहा कि सब सुरक्षित हैं। आज पहले ये बताएं कि किस तरह से जल, जंगल, जमीन को खतरा है। राजनीतिक रूप से बात ना करके सही कारण बतायेंगे तो बहस करेंगे। बस्तरवासी अब जब



स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं, तो उन्हें दिक्कत हो रही है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्षों के बाद अब ब्लॉक अध्यक्ष की ट्रेनिंग पर विधायक चंद्राकर ने कहा कि जो ट्रेनर हैं, वो अपने-अपने इलाके में प्लॉप शो वाले हैं। कैसे प्लॉप हुई, इस पर बताएं कि किस तरह से जल, जंगल, जमीन को खतरा है। राजनीतिक रूप से बात ना करके सही कारण बतायेंगे तो बहस करेंगे। बस्तरवासी अब जब

जाते हैं। ये कोन सा मॉडल हैं? जो ट्रेनिंग ये यहाँ देंगे, ये समझ से बाहर हैं। ये ट्रेनिंग हार का मॉडल है। वहीं शक्कर के बढते दामों को लेकर कांग्रेस ने पोस्टर जारी कर भाजपा पर डायबिटीज मुक्त भारत योजना बनाने का आरोप लगाया है। इस पर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि जो भी परिस्थितियाँ हैं, सामने है। सरकार मूल्य पर नियंत्रण भी कर रही है। कांग्रेस नेताओं को सब चीज छोड़कर मनुस्मृति पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी का ध्यान मनुस्मृति में है। तथाकथित महंगाई में नहीं है। सनातन के मुख्य ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो तोड़-मरोड़ कर बात पेश नहीं करेंगे। इसके अलावा रायपुर सहित देश के 11 एयरपोर्ट का निजीकरण

पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर अजय चंद्राकर का पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में निजीकरण कितना हुआ है? कौन देश में निजीकरण लाया? मनमोहन सिंह जी का क्या रोल है देश के निजीकरण में? जिस सिद्धांत के वह प्रणेता है उसका विरोध करते हैं। क्या कांग्रेस मनमोहन सिंह की नीतियों का विरोध कर रही है? कांग्रेस का जो मतिभ्रम है। वही उसके विनाश का कारण है। वहीं महतारी वंदन की राशि जारी करने के दौरान बारिश को लेकर मंत्री से सांसद सांसद भोजराज नाग के नींबू काटने वाले वायरल बयान पर बीजेपी वरिष्ठ नेता ने कहा कि सावन महीने में हरेली से तंत्र-मंत्र होता है। जिसकी जो आस्था है, उसे करने दो।



मेल और आपत्ति का कारण देना होगा। साथ ही यह भी बताना होगा कि संबंधित व्यक्ति जनसुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहता है या नहीं। टाटा पावर के आवेदन और संबंधित दस्तावेज आयोग और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। कार्यालय से दस्तावेजों की प्रति 500 रुपये में प्राप्त की जा सकती है। आपत्ति की छह प्रतियां शपथ-पत्र के साथ आयोग के सचिव को जमा करनी होंगी और एक प्रति टाटा पावर को भी भेजना जरूरी होगा। फिलहाल रायपुर और प्रस्तावित क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यदि नियामक आयोग से टाटा पावर को अनुमति मिलती है, तो इन क्षेत्रों में बिजली वितरण के लिए एक और कंपनी के काम करने का रास्ता खुल सकता है। इससे उपभोक्ताओं को सेवा, शिकायतों के निराकरण, नए कनेक्शन और अन्य सुविधाओं के मामले में विकल्प मिल सकते हैं।

<

भाजपा में संगठनात्मक फेरबदल बाकी है !

हरीश गुप्ता

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को नई संगठनात्मक टीम में 65 में से 51 चेहरे नए हैं। महीनों की राजनीतिक उठापटक, विचार-विमर्श और गणनाओं के बाद आखिरकार लंबे समय से प्रतीक्षित टीम सामने आ गई है। फिर भी राजनीतिक विश्लेषक यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि यह कोई बड़ा बदलाव है या फिर महज ‘चू-चू का सुरूब्या’ – यानी अलग-अलग और बेमेल चीजों को एक साथ मिला देने जैसा प्रयोग। स्मृति ईरानी और राम माधव की पुनः नियुक्ति और विनोद तावड़े की बड़ी पदोन्नति के अलावा, ऐसा कुछ खास नहीं है जिसे राजनीतिक उथल-पुथल कहा जा सके। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि असली फेरबदल अभी बाकी है। इसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि जिन कई मंत्रियों के सरकार से संगठन में जाने की उम्मीद थी, वे अभी भी अपने पदों पर बने हुए हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड का भी अब तक पुनर्गठन नहीं हुआ है। केंद्रीय चुनाव समिति का भी पुनर्गठन नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो संगठनात्मक फेरबदल अभी पूरा नहीं हुआ है। और फिर आती है सरकार। मंत्रोगण – और सत्ता की सीढ़ी पर चढ़कर उम्मीद लगाए बैठे राजनीतिक नेता – महीनों से दूसरे चरण का इंतजार कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल, चाहे जब भी हो, कहीं अधिक नाटकीय हो सकता है। माना जा रहा है कि कम-से-कम दो दर्जन मंत्री या तो हटाए जा सकते हैं या उनके विभाग बदले जा सकते हैं। संगठन में जगह पाने से चूक गए कुछ प्रमुख नेताओं को इसके बजाय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जल्दबाजी की वजह भी साफ है। कई मंत्री पहले से ही तीन-तीन मंत्रालय संभाल रहे हैं, जिससे सरकार एक सुचारू तंत्र की भांति प्रयोग ‘एक व्यक्ति, तीन मंत्रालय’ वाले तमाम्बे जैसी दिखने लगी है। तो अभी हुआ क्या है? शायद यह भाजपा के फेरबदल का पहला चरण मात्र है। दूसरा चरण अभी आना बाकी है। 2019 में महाराष्ट्र राज्य की राजनीति से बाहर निकलने के बाद कई वर्षों तक राजनीतिक रूप से हाशिए पर रहने के बाद विनोद तावड़े ने एक उल्लेखनीय वापसी की है। प्रमुख ओबीसी नेता तावड़े अब भाजपा की सत्ता संरचना में कोई हाशिए का चेहरा नहीं हैं; उन्हें तेजी से पार्टी के प्रमुख संकटमोचकों में गिना जाने लगा है। तावड़े भाजपा के महासचिव रह चुके हैं और बिहार का दायित्व भी संभाल चुके हैं। हालाँकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का काफी श्रेय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री धर्मदे प्रधान को दिया गया, जो राज्य के चुनाव प्रभारी थे। अब तावड़े को भाजपा की राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी – उत्तर प्रदेश – सौंपी गई है। उनकी पदोन्नति बहुत कुछ कहती है। भाजपा के आठ महासचिवों में तावड़े को संगठनात्मक वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखा गया है, जबकि स्मृति ईरानी चौथे स्थान पर हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, शीर्ष नेतृत्व ने तावड़े से विशेष रूप से पूछा था कि वे संगठन में काम करना पसंद करेंगे या सरकार में शामिल होना। उन्होंने पार्टी को चुना और इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का दायित्व मिला जिसे 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का राजनीतिक वाटरल् माना जा रहा है। दांव बहुत बड़ा है। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े ‘चंदा चोरी’ विवाद और काँजपा के रूप में उभरती जैन-जी ने भाजपा की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल अब राजनीतिक कवायद से ज्यादा शुभ मुहूर्त की तलाश बन गया है। अटकलें थपने का नाम नहीं ले रही हैं, और राजनीतिक गलियारों में अब अगस्त में किसी एक संभावित तिथि पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है या नवरात्रि तक इंतजार करने का विकल्प है। जानकारी के अनुसार, 20 नवंबर तक इस तरह की बड़ी राजनीतिक कवायद के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है।

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

व्याकरण शास्त्र

पिछले दिनों काशी से प्रकाशित होने वाले सुप्रभातम् संस्कृत पत्र में स्वर्गीय श्री कविचक्रवर्ती देवीप्रसाद जी शुक्ल का बनाया हुवा श्लोक तद्ध व्याकरण छपता था। हम उसे बड़े चाव से पढ़ा करते थे, और वह इसलिए कि– वैयाकरण श्रुतिकट्ट कर्कशभाषी होते हैं– ऐसा लोक-प्रवाद चला आता है। पाणिनि के टिड्डणा ने और मुरारिकविकृत अनर्घ–राघव के तताटूक आदि पयों ने इस प्रवाद को और भी दृढ़ बना रक्खा है। कविचक्रवर्ती जी ने उसे सुललित शब्दों में बाँधने का प्रयत्न किया था। हमें हर्ष था किचलो अब शुष्को वृक्षस्तिवेल्लग्रे के स्थान में नीरसतरुह्रि विलसति पुरतः हो जायगा। जो कि शब्दन सौन्दर्योपासकों के मनोविनोद का पयसि साधन सिद्ध होगा। परन्तु जब हमने अग्निपुराण का परायण किया तो (346 अध्याय से 356 अध्याय पर्यन्त)

श्लोकबद्ध व्याकरण प्राप्त हो गया जिसे देखकर हम फूले नहीं समाये, और कवि-चक्रवर्ती जी के प्रयत्न को प्रयास मात्र समझा। जो सञ्जन उत्सुक हों वहां देखकर लाभ उठाएं। इस तरह पुराणों में व्याकरण–शास्त्र का भी समावेश विद्यमान है ।

अलंकार शास्त्र

पं0 अलंकार शास्त्र का मूल अग्निपुराण है– यह बात सभी अलंकार-धुरन्धरों ने स्वीकार की है। चतुर्दश-भाषा-वारविद्यासिनीभुञ्जम्न विश्वनाथ जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ साहित्यदर्पण के आरम्भ में ही इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है। अग्निपुराण में गुण, दोष, अलङ्कार नाटकादि भेद, एव नायक नायिका भेद, गर्ज है कि साहित्य सम्बन्धो सभी बातों का विशद विवेचन किया गया है, इसलिये हम अग्निपुराण l-णित इस प्रषष्ट को साहित्य कल्पतरु का बीज कह दें तो अत्युक्ति न होगी।

क्रमशः ...



नेहरू ने चीन को बोला था भाई वो निभाता रहा दुश्मनी!

नीरज कुमार दुवे

नेहरू ने जिस चीन को कभी ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ के नारे के साथ गले लगाया था, उसने भारत के साथ दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी निभाई। 1962 की धोखाधड़ी से लेकर गलवान की खूनी झड़प तक, सीमा पर तनाव, भुसपैठ और सामरिक दबाव, बीजिंग का ट्रैक रिकॉर्ड भारत के सामने साफ है। लेकिन अब वही चीन दोस्ती, स्थिरता और सहयोग की भाषा बोलते हुए दिल्ली आने की तैयारी कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने की संभावना है। यहां सवाल यह है कि क्या चीन वास्तव में रिश्ते सुधारना चाहता है, या बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत के साथ सामरिक समीकरण को अपने हित में ढालना चाहता है? माना जा रहा है कि शी जिनपिंग 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ सकते हैं। यह यात्रा कई मायनों में असाधारण होगी। यदि यह योजना अंतिम रूप लेती है तो शी जिनपिंग करीब सात साल बाद भारत आएंगे। इस यात्रा की सबसे दिलचस्प बात उनके साथ आने वाला विशाल चीनी प्रतिनिधिमंडल है। बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग के साथ करीब 400 अधिकारी भारत आ सकते हैं। यह संख्या उनकी 2019 की भारत यात्रा के दौरान आए चीनी अधिकारियों की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है। उस समय प्रतिनिधिमंडल में 200 से कम अधिकारी शामिल थे।

भारतीय सूत्रों के अनुसार, चीनी अधिकारी होटल, सुरक्षा व्यवस्था और यात्रा से जुड़े प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। हालांकि शी जिनपिंग की यात्रा योजना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संभावित द्विपक्षीय बैठक का एजेंडा अभी अंतिम रूप नहीं ले पाया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी फिलहाल यात्रा की औपचारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि चीन ब्रिक्स सहयोग को बहुत महत्व देता है और भारत की अध्यक्षता में



होने वाले इस वर्ष के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता का समर्थन करता है। यानी संदेश साफ है कि बीजिंग अभी अंतिम घोषणा से बच रहा है, लेकिन दिल्ली की दिशा में उसकी कूटनीतिक गतिविधियां तेज हैं।

उधर, शी जिनपिंग की संभावित यात्रा से पहले भारत और चीन के बीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक संपर्क तेज हो गए हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत-चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधि अजित डोभाल बीजिंग में हैं। 25 अगस्त को डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत-चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के 25वें दौर में भी हिस्सा लिया। इन वार्ताओं में केवल सीमा विवाद ही नहीं, बल्कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

यहां भारत की रणनीति को समझना बेहद जरूरी है। दिल्ली ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत-चीन संबंधों को केवल व्यापार, ब्रिक्स या बहुपक्षीय सहयोग के सहारे सामान्य नहीं बनाया जा सकता। सीमा पर शांति और स्थिरता ही व्यापक रिश्तों की बुनियाद होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत अब 1962 से पहले वाली उस कूटनीतिक भूल को दोहराने के मूड में नहीं दिखता, जिसमें राजनीतिक दोस्ती के नारों के बीच सामरिक खतरे को

ज्ञान/मीमांसा

अंतरिक्ष में भारत की निजी शक्ति एवं वैज्ञानिक सामर्थ्य की उड़ान

ललित गर्ग

भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब केवल सरकारी संस्थानों और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रह गई है। यह यात्रा आज नवाचार, उद्यमिता, युवा प्रतिभा, निजी पूंजी और वैश्विक महत्वाकांक्षा के ऐसे संगम में बदल रही है, जिसने भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की दिशा में एक नई गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी सहभागिता के द्वार खोलने का निर्णय इसी परिवर्तन का निर्णायक पड़ाव है। कभी जिस अंतरिक्ष क्षेत्र को लगभग पूरी तरह सरकारी नियंत्रण और संस्थागत सीमाओं के भीतर देखा जाता था, आज वहां सैकड़ों नवोदित उद्यम अपने सपनों, तकनीक और साहस के साथ नई संभावनाओं का आकाश तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय निजी अंतरिक्ष उद्यमियों से संवाद कर उन्हें प्रेरित करना केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भविष्य के भारत की दिशा का उद्घोष है।

इसमें उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ भारत को विश्व की अंतरिक्ष प्रतिभा, निवेश और उद्यमिता का आकर्षण-केंद्र बनाने का सपना प्रस्तुत किया, वह भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का भी संकेत है। भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का इतिहास अपने आप में असाधारण है। सीमित संसाधनों के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जिस वैज्ञानिक अनुशासन, आत्मनिर्भरता और संकल्प का परिचय दिया, उसने दुनिया को चकित किया है। आर्यभट्ट से प्रारंभ हुई यात्रा मंगलयान तक पहुंची, चंद्रयान ने चंद्रमा के रहस्यों को समझने की भारतीय क्षमता सिद्ध की और चंद्रयान-3 ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बनाकर इतिहास रचा। यह उपलब्धि केवल एक वैज्ञानिक सफलता नहीं थी, यह भारतीय प्रतिभा, तकनीकी आत्मविश्वास और असंभव को संभव करने की राष्ट्रीय क्षमता का प्रमाण थी। मंगलयान ने कम लागत में अंतरग्रहीय अभियान की सफलता से दुनिया को भारत की वैज्ञानिक दक्षता का परिचय दिया। आदित्य-एल1 ने सूर्य के अध्ययन की दिशा में भारत की महत्वाकांक्षा को नई ऊंचाई दी। अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति की तैयारी से जुड़ा गगनयान अभियान भारत की अगली बड़ी छलांग का संकेत है। इस पूरी यात्रा ने यह स्पष्ट किया है कि भारत अब अंतरिक्ष विज्ञान में केवल उपलब्धियों का अनुकरण करने वाला देश नहीं, बल्कि नए मानदंड स्थापित करने की क्षमता रखने वाला राष्ट्र है।

इस उपलब्धि की अगली स्वाभाविक कड़ी निजी क्षेत्र की भागीदारी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद भारत में लगभग 440 अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी नवोदित उद्यमों का उभरना इस परिवर्तन की गहराई को दर्शाता है। इनमें कुछ उपग्रह निर्माण में लगे हैं, कुछ प्रक्षेपण यानों की तकनीक विकसित कर रहे हैं, कुछ अंतरिक्ष आधारित आंकड़ों के विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पृथ्वी अवलोकन, संचार, मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन जैसी अत्याधुनिक दिशाओं में काम कर रहे हैं। स्काईरूट एयरोस्पेस ने निजी क्षेत्र के रॉकेट प्रक्षेपण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है, जबकि अग्निकुल कॉस्मॉस ने स्वदेशी तकनीक और आधुनिक निर्माण पद्धतियों के माध्यम से यह दिखाया है कि भारतीय निजी उद्यम अंतरिक्ष प्रक्षेपण के कठिन क्षेत्र में भी अपनी जगह बना सकते हैं। ये प्रयास उस मानसिकता को बदल रहे हैं जिसमें अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों का क्षेत्र माना जाता था। अब यह युवा उद्यमियों के लिए रोजगार, अनुसंधान, निवेश और वैश्विक व्यापार का नया क्षेत्र बन रहा है। इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अंतरिक्ष अब केवल आकाश में उपलब्धियों का विषय नहीं, बल्कि धरती पर जीवन को बेहतर बनाने का साधन भी बन रहा है। उपग्रह आधारित सेवाएं कृषि की उत्पादकता बढ़ाने, फसल की निगरानी करने, जल संसाधनों की पहचान, मौसम की सटीक जानकारी देने, मछली पालन, वन संरक्षण और आपदा प्रबंधन में उपयोगी हो सकती हैं। बाढ़, चक्रवात, सूखा और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय अंतरिक्ष से प्राप्त सूचनाएं राहत और बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बना सकती हैं। गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में संचार तथा डिजिटल सेवाओं के विस्तार

संगीत की दुनिया में मुकेश ने बनाया था अलग मुकाम

अनन्या मिश्रा

हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे लोकप्रिय और पार्श्व गायकों में से एक रहे मुकेश का 27 अगस्त को निधन हो गया था। मुकेश द्वारा गाए गीत लोग आज भी गुनगुनाना पसंद करते हैं। उन्होंने अपने जमाने के कई दिग्गज कलाकारों को आवाज दी थी। जिनमें से मनोज कुमार, राज कपूर, सुनील दत्त, फिरोज खान और दिलीप शामिल हैं। मुकेश एक पार्श्व गायक थे।

मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को हुआ था। उनका पूरा नाम मुकेश चंद माथुर था। इनके पिता जोरावर चंद माथुर एक इंजीनियर थे। संगीत शिक्षक मुकेश की बहन सुंदर प्यारी को पढ़ाने के लिए घर आते थे। लेकिन उनको मुकेश में अपना शिष्य मिला। मुकेश ने 10वीं के बाद

अपनी पढ़ाई छोड़ दी और दिल्ली जाकर नौकरी करने लगे। इस दौरान वह वॉइस रिकॉर्डिंग का भी प्रयास करने लगे और धीरे-धीरे अपनी गायन क्षमता को विकसित किया।

एक्टर और प्रड्यूसर मोतीलाल ने सबसे पहले मुकेश की आवाज पर ध्यान दिया था। जिसके बाद मोतीलाल ने मुकेश को पंडित जगन्नाथ प्रसाद से गायन की शिक्षा दिलवाई। फिर साल 1941 में आई फिल्म निर्दोष में उनको पहला गाना दिल हो बुझा हुआ हो तो गाने का मौका मिला। बतौर पार्श्वगायक यह मुकेश का पहला हिट गाना था। फिर साल 1945 में उन्होंने फिल्म पहली नज़ में गाना दिल जलता है तो जलने दो गाया था।



वैसे तो मुकेश ने अपने जमाने के सभी लीड एक्टर्स के लिए गाने गाए हैं। लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा गाने शोमैन राज कपूर के लिए गाए हैं। इनमें से जीना यहां मरना यहाँ, दुनिया बनाने वाले, आवा़ा हूं, दोस्त-दोस्त ना रहा, सज़न रे झूठ

मत बोलो, कहता है जोकर और मेरा जूता है जापानी, एक प्यार का नगमा है, मैं पल दो पल का शायर जैसे सदाबहार गानों को अपनी आवाज़ देने वाले मुकेश एक ऐसे गायक थे, जिन्हें दर्द भरे गानों से इश्क था। वह कहते थे कि वह 10 नॉर्मल गानों को छोड़कर एक दर्द भरा सॉनग गाना पसंद करते हैं। उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था कि वह अपने समय में सभी सिंगर्स के भारी पड़ गए थे।

40 के दशक में मुकेश ने अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने 1300 से भी ज्यादा गाने गाए। उन्होंने सबसे ज्यादा गाने राज कपूर के लिए गाए थे, इसी वजह से उन्हें राज कपूर की आवाज़ भी कहा जाने लगा। मुकेश की गायिकी की दीवानगी आज भी लोगों में कम नहीं है। सुरों के सरताज मुकेश के गाने जितने बेहरीन थे, उनकी निजी जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प थी।

मुकेश ने अपने अंतिम समय तक म्यूजिक का साथ नहीं छोड़ा। मुकेश का निधन 27 अगस्त 1976 को 53 साल की उम्र में अमेरिका में एक स्ट्रेज शो के दौरान हुआ था। उन्हें कॉन्सर्ट के बीच हार्ट अटैक आया था। कहा जाता है कि जब मुकेश को हार्ट अटैक आया, उस वक्त वह स्ट्रेज पर इक दिव बिज जाएगा माटी के मोल गाना गा रहे थे।



में भी अंतरिक्ष तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब केवल वैज्ञानिक गौरव का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास का शक्तिशाली माध्यम बन रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतरिक्ष संबंधी दृष्टिकोण इसी व्यापक सोच का आधारित दिखाई देता है। उनका सपना भारत को केवल

अंतरिक्ष में पहुंचने वाला देश बनाना नहीं, बल्कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अग्रणी शक्ति बनाना है। वे चाहते हैं कि दुनिया की प्रतिभाएं भारत आएँ, भारतीय युवा अंतरिक्ष क्षेत्र में नए विचारों के साथ आगे बढ़ें और भारत वैश्विक अंतरिक्ष कंपनियों तथा निवेशकों के लिए विश्वसनीय केंद्र बने। यह दृष्टिकोण भारत की आर्थिक शक्ति को नई दिशा दे सकता है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में संचार, मौसम, रक्षा, कृषि, परिवहन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सेवाओं के साथ गहराई से जुड़ने वाली है। ऐसे में जो देश इस क्षेत्र में तकनीकी नेतृत्व स्थापित करेगा, उसकी आर्थिक और रणनीतिक शक्ति भी बढ़ेगी। निजी अंतरिक्ष उद्यमों के सामने संभावनाएं जितनी बड़ी हैं, चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर हैं। अंतरिक्ष तकनीक में अनुसंधान और विकास के लिए भारी पूंजी चाहिए। प्रक्षेपण की असफलता का जोखिम सामान्य उद्योगों की तुलना में कहीं अधिक होता है। अत्यंत जटिल तकनीक, कठोर सुरक्षा मानक, कुशल मानव संसाधन और दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता इस क्षेत्र को कठिन बनाती है। इसलिए सरकार की भूमिका केवल नियम बनाने तक सीमित नहीं रह सकती। उसे ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो नवाचार को प्रोत्साहित करें, निजी उद्यमों को परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएं, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाएं तथा निवेशकों का विश्वास कायम रखें। अंतरिक्ष क्षेत्र की एकल खिड़की व्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार कर रही हैं।

भारत के लिए एक और बड़ी संभावना अंतरिक्ष में लागत और दक्षता की अपनी पारंपरिक ताकत को वैश्विक बाजार से जोड़ना है। भारत ने पहले ही यह सिद्ध किया है कि सीमित

लागत में उच्च गुणवत्ता वाली अंतरिक्ष सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। यदि यही क्षमता निजी क्षेत्र की गति, नवाचार और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति से जुड़ती है तो भारत छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण, उपग्रह निर्माण, अंतरिक्ष आधारित आंकड़ों और वैश्विक अंतरिक्ष सेवाओं के क्षेत्र में बड़ा बाजार हासिल कर सकता है। इससे विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ-साथ उच्च कोशल वाले रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अनुभव निजी क्षेत्र के लिए अमूल्य पूंजी है। दशकों की वैज्ञानिक साधना से अर्जित ज्ञान, प्रक्षेपण तकनीक, उपग्रह निर्माण की क्षमता और मिशन प्रबंधन का अनुभव अब देश के नवोदित उद्यमों के लिए मार्गदर्शक शक्ति बन सकता है। सरकारी संस्थान और निजी उद्यम यदि प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग की संस्कृति विकसित करें तो भारत की अंतरिक्ष शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। सरकार का काम रास्ता खोलना है, वैज्ञानिक संस्थानों का काम ज्ञान और अनुभव उपलब्ध कराना है और निजी क्षेत्र का काम गति, नवाचार और बाजार की शक्ति को आगे बढ़ाना है। इन तीनों का समन्वय भारत को नई ऊंचाई दे सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी का यह आह्वान कि भारत ऐसा वातावरण बनाए जहां दुनिया भर के युवा अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के लिए यहाँ आने की सोचें, वास्तव में प्रतिभा की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की नई आकांक्षा को व्यक्त करता है। यह केवल रॉकेटों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य नहीं है, यह भारत को अंतरिक्ष आधारित ज्ञान, तकनीक और अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने की कल्पना है। आने वाले समय में अंतरिक्ष में भारत की सफलता का मूल्यांकन केवल कितने उपग्रह भेजे गए या कितने रॉकेट छोड़े गए, इससे नहीं होगा। असली कसौटी यह होगी कि अंतरिक्ष तकनीक ने भारतीय किसान, विद्यार्थी, उद्यमी, सैनिक, वैज्ञानिक और सामान्य नागरिक के जीवन को कितना बेहतर बनाया। भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब उस मुकाम पर है जहां आकाश सीमा नहीं, बल्कि अवसर है। चंद्रयान-3 की चंद्र विजय से लेकर सूर्य की ओर आदित्य-एल1 की यात्रा, मंगलयान की ऐतिहासिक सफलता से लेकर मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी और सरकारी संस्थानों से निकलकर निजी स्टार्टअप के प्रक्षेपण तक भारत ने लंबी दूरी तय की है। अब अगला अध्याय और अधिक महत्वाकांक्षी होना चाहिए।

आज का इतिहास

1604 अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आदि गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिस्थापना की गई।

1781 हैदर अली ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ पल्लीलोर का युद्ध लड़ा। 1859 देश के महान उद्योगपति दाराबजी टाटा का जन्म हुआ था। उन्होंने ही टाटा स्टील की नींव रखी थी।

1870 भारत के पहले मजदूर संगठन के रूप में श्रमजीवी संघ की स्थापना की गई।

1907 सदी के महानतम क्रिकेटर सर डॉन जॉर्ज ब्रैडमैन का जन्म हुआ था।

1939 जेट ईधन वाले विश्व के पहले विमान ने जर्मनी से पहली उड़ान भरी।

1972 भारतीय प्रोफेशनल रेसलर और लिफ्टर दलीप सिंह राणा का जन्म हुआ। वह ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध हैं।

1976 भारतीय सशस्त्र सेना की प्रथम महिला जनरल मेजर जनरल जी अली राम मिलिट्री नर्सिंग सेवा की निदेशक नियुक्त हुई।

1982 भारत ने कारगिल संघर्ष के दौरान अपने यहाँ बंदी बनाये गये पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा किया।

1985 नाइजीरिया में सैनिक क्रांति में मेजर जनरल मुहम्मद बुहारी की सरकार का तख्ता पलटा गया तथा जनरल इब्राहिम बाबनगिदा नये सैनिक शासक बने।

1990 वार्शिंगटन स्थित इराकी दूतावास के 55 में से 36 कर्मचारियों को अमेरिका ने निष्कासित कर दिया।

1991 मालदीवा ने सोवियत संघ से आजाद होने की घोषणा की।

1999 सोनाली बनर्जी भारत की प्रथम महिला मैरिन इंजिनयर बनीं।

1999 भारत ने कारगिल संघर्ष के दौरान अपने यहाँ बंदी बनाये गये पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा किया।

2003 60 हजार वर्षों के अंतराल के बाद मंगल पृथ्वी के सबसे नजदीक पहुंचा।

2004 निजमती शौकत अजीज पाकिस्तान के नये प्रधानमंत्री चुने गये।

2008 सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिश् ए.के. माथुर को सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल का पहला अध्यक्ष बनाया गया।

2008 झारखण्ड मुक्तिमोर्चे के प्रमुख शिवु सोरेन ने झारखण्ड के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

2009 बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष सुश्री मायावती को पुनः अध्यक्ष पद पर तीसरी बार चुन लिया गया। उल्लेखनीय है कि दल के संस्थापक काशीराम के उपरान्त वे लगातार इस पद पर बनी हुई हैं

2013 उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दो धार्मिक समुदायों के बीच दंगे भड़के।

1947 में लिए गये कांग्रेस के गलत फैसले की कीमत आज भी चुका रहा है भारत

नीरज कुमार दुबे

1947 का भारत विभाजन इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। लाखों लोग अपने घर-परिवार, जमीन-जायदाद छोड़ने पर मजबूर हुए, लाखों लोगों की हत्या हुई और करोड़ों लोग विस्थापन की त्रासदी से जूझे। यह एक ऐसा स्थायी घाव था, जो आज भी भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करता है।देखा जाये तो कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने अंग्रेजों द्वारा पेश किए गए विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर ऐतिहासिक भूल की थी, जिसकी कीमत देश आज भी चुका रहा है।

14 अगस्त को मनाया जाने वाला विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसी त्रासदी की मानवीय कीमत को याद करने का अवसर है। भारत सरकार ने 2021 में इस दिवस की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य केवल उन लोगों को श्रद्धांजलि देना नहीं है, जिन्होंने जान गंवाई या अपना घर छोड़ा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह समझाना भी है कि सांप्रदायिक नफरत, हिंसा और राजनीतिक विभाजन किस भयावह परिणाम तक पहुंच सकते हैं।

हम आपको याद दिला दें कि 1947 में विभाजन के समय पंजाब और बंगाल सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में रहे। परिवार बिछड़े,

गांव और संपत्तियां सीमा के दो हिस्सों में बंट गईं और लाखों लोगों को अचानक अनिश्चित भविष्य की ओर पलायन करना पड़ा। विभाजन के कारणों को लेकर इतिहास में अलग-अलग व्याख्याएं देखने को मिलती हैं। मुस्लिम लीग की दो-राष्ट्र सिद्धांत की राजनीति, पाकिस्तान नामक अलग देश की मांग, सांप्रदायिक तनाव और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति इसके प्रमुख संदर्भ रहे। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना की घोषणा की और इसके बाद रैडक्लिफ आयोग ने भारत-पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की। सीमाएं इतनी तेजी से खींची गईं कि लाखों लोग अपनी जमीन, पहचान और सुरक्षा को लेकर असमंजस में पड़ गए।

यहीं से कांग्रेस नेतृत्व के फैसले पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मांग और ब्रिटिश जल्दबाजी के सामने विभाजन स्वीकार करके उस विचार को अप्रत्यक्ष मान्यता दी कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। वहीं विभाजन समर्थक इतिहासकारों का कहना है कि उस समय व्यापक हिंसा, राजनीतिक गतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की वापसी की जल्दबाजी के बीच एकीकृत भारत को बनाए



रखना अत्यंत कठिन हो चुका था। इसलिए यह बहस आज भी जारी है कि क्या विभाजन टाला जा सकता था या वह उस समय की परिस्थितियों का लगभग अपरिहार्य परिणाम बन चुका था।

विभाजन की राजनीतिक कीमत के साथ इसकी भू-राजनीतिक कीमत भी सामने आई। पाकिस्तान के अस्तित्व ने भारत के पश्चिमी

अतिरिक्त दबाव डाला और रक्षा व्यय का बड़ा हिस्सा इस चुनौती से निपटने में लगा।

महात्मा गांधी का दृष्टिकोण भी इस पूरी कहानी को एक अलग नैतिक आयाम देता है। वह धर्म के आधार पर देश के विभाजन के विरोधी थे और ऐसी स्वतंत्रता चाहते थे, जिसमें शांति, सद्भाव और समानता हो। 15 अगस्त 1947 को उनका दिल्ली के सत्ता-केंद्रित समारोहों में शामिल नहीं होना इसी पीड़ा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वह मानते थे कि यह वह 'पूर्ण स्वतंत्रता' नहीं थी जिसके लिए उन्होंने सत्याग्रह और असहयोग आंदोलनों की अगुवाई की थी।

साथ ही, इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों ने जिन देशों में विभाजन कराया उनमें भारत का विभाजन ही सबसे रक्तरंजित रहा। लाखों जानें गईं, करोड़ों लोग बेघर हुए और पीढ़ियों तक घाव ताजा रहे। यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कांग्रेस का तत्कालीन नेतृत्व अंग्रेजों की चाल और उनकी 'फूट डालो, राज करो' नीति को भली-भांति समझता था, तब भी उन्होंने विभाजन का खुलकर विरोध क्यों नहीं किया था? क्या यह

राजनीतिक थकान थी, साम्प्रदायिक हिंसा के दबाव में लिया गया समझौता था? या फिर सत्ता तक शीघ्र पहुंचने की अधीरता थी? जो भी कारण रहे हों, उनका परिणाम आज भी भारत भुगत रहा है। देखा जाये तो इतिहास के उस मोड़ पर लिया गया निर्णय न केवल तत्कालीन पीढ़ी के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्थायी संकट का कारण बन गया।बहरहाल, 79 साल बाद भी विभाजन के सवाल खत्म नहीं हुए हैं। कश्मीर, सीमा पार आतंकवाद, रक्षा बोझ, सामाजिक अविश्वास और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे इस इतिहास की लंबी छाया की याद दिलाते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि राजनीतिक फैसलों के परिणाम केवल तत्कालीन पीढ़ी तक सीमित नहीं रहते। इसलिए 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस केवल शोक का दिन नहीं, बल्कि आत्ममंथन का दिन भी है। साथ ही उन लाखों लोगों को नमन करने का दिन भी है जिन्होंने अपनी जान, घर और पहचान खोई; और यह संकल्प लेने का दिन भी है कि इतिहास की त्रासदियों को दोहराने की बजाय उनसे सीख लेकर भारत की एकता, सामाजिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को और मजबूत किया जाए।

आतंकवाद के लिए खाद पानी है नशीले द्रव्यों की तस्करी!

मनोज कुमार अग्रवाल

भारत में नशीले पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी देश की आंतरिक सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए एक अत्यंत गंभीर संकट बन चुकी है। भौगोलिक रूप से भारत दुनिया के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों – पश्चिम में गोल्डन क्रेंसेंट (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान) और पू्व में गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार, लाओस, थाईलैंड) के बीच स्थित है। इस संवेदनशील स्थिति के कारण देश में सीमा पार से बड़े पैमाने पर अवैध नशीले पदार्थों की आमद हो रही है। नशीले पदार्थों की तस्करी में भारत की भौगोलिक स्थिति भी खासा जिम्मेदार है पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार से सटी खुली और जटिल जमीनी सीमाएं निगरानी के लिए एक बड़ी चुनौती है। तस्करों द्वारा गुजरात और दक्षिणी राज्यों के विशाल तटीय क्षेत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है।अब नशे के सौदागर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं।डार्कनेट क्रिप्टो करेंसी और सीमा पार से ड्रग्स गिराने के लिए ड्रोन का बढ़ता प्रयोग खतरा बढ़ा रहे हैं।वहीं पारंपरिक अफीम-गांजे के स्थान पर हेरोइन, कोकीन और मैथामफेटामाइन जैसे घातक रसायनों सिंथेटिक ड्रग्स का बढ़ता चलन भी समस्या बन रहा है। आपको बता दें कि देश में नशे और नशीले पदार्थों की तस्करी ने एक बार फिर केन्द्र और राज्यों की सरकारों को ख़तब्य किया है। नशीले पदार्थों की यह तस्करी का बड़ा हिस्सा पड़ोसी देश पाकिस्तान के माध्यम से सीमा पार से ड्रोंनों के ज़रिये किया जाता है। नशे को लेकर किये गये एक व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार पाकिस्तान एक प्रकाश से नशीले पदार्थों के भण्डारण का केन्द्र बन गया है जहां से इन पदार्थों का बहुत बड़ा भाग भारत के पंजाब प्रांत में ड्रोंनों के ज़रिये खपाया जाता है। भारत से फिर यह सामान तस्करी के ज़रिये कई अन्य देशों में भेजा जाता है जहां इसकी बड़ी मांग होती है। पाकिस्तान से भारत में पंजाब सीमा के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी यूं तो दशकों पूर्व से की जाती आ रही है। कभी नावों के माध्यम से, कभी सुरंगों के ज़रिये पाकिस्तानी पंजाब के सीमा-पार से भारतीय पंजाब

में अफीम और हेरोइन की तस्करी की जाती रही है। तथापि, आजकल नावों का कार्य ड्रोंनों से लिया जाने लगा है। ड्रोंनों के ज़रिये पाकिस्तानी सीमा-पार से भारतीय पंजाब में अफीम, हेरोइन के साथ हथियारों की खेप भेजना जैसे आम बात हो गई है।वैसे तो नशे के लिए अफीम, चरस, कोकीन आदि अनेकानेक द्रव्यों एवं पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है किन्तु वर्तमान में हेरोइन सर्वोत्तम नशीला पदार्थ बन गया है। हाल ही में एक और बड़ा खतरनाक नशीला पदार्थ आईस भी बड़ी चर्चा में आया है। विगत कई वर्षों से हेरोइन की तस्करी और इसके सेवन की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हुई है। इसका बड़ा प्रमाण इस एक तथ्य से मिल जाता है कि इन दिनों सीमाओं पर विशेष सुरक्षा चौकसी होने के बावजूद तस्करी से बरामद होने वाली खेपों की संख्या और मात्रा बढ़ गई है। इसके लिए तस्करों द्वारा अत्याधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाने लगा है। सीमा सुरक्षा बलों की निरन्तर चौकसी और सतर्कता के बावजूद ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले पांच वर्षों में पंजाब सीमा पर ड्रोन तस्करी की घटनाएं बढ़ कर तीन से 304 प्रति वर्ष तक हो गई हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में स्थितियों की गम्भीरता को पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा की गई इस एक कठोर टिप्पणी से बेहतर समझा जा सकता है कि नशे का यह सम्पूर्ण कारोबार महज़ एक आपराधिक कार्य मात्र नहीं रह गया, अपितु राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। यूं तो नशे के सेवन और नशीले पदार्थों की तस्करी से गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे प्रदेश बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं किन्तु पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। प्रदेश के युवाओं में नशे की समस्या एक गम्भीर संकट के रूप में उभर रही है। पंजाब सरकार की पुनर्वास योजनाओं के तहत प्रदेश का पुलिस तंत्र युवाओं को इस महारोग से बचाने के लिए भरसक यत्न कर रहा है। किन्तु यह समस्या एक ऐसे बिगड़ैल घोड़े के समान हो गई है कि जिसकी नाक में आसानी से नकेल नहीं डाली जा सकती।

वन्देमातरम् : क्या कांग्रेस जिन्ना के मार्ग पर जा रही है?

सुरेश हिंदुस्तानी

वन्देमातरम आज विवाद का विषय बना दिया है। जबकि यह सत्य है कि जब बंकिम बाबू ने इसकी रचना की थी, तब उनके मन में किसी के मन को आहत करने का कोई विचार नहीं था। उनका भाव केवल मातृभूमि के वंदन का था। देश में वन्देमातरम के अंतिम दो भाग का पहली बार विरोध विभाजन की मानसिकता रखने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। आज उसी मार्ग पर कांग्रेस कदम बढ़ाती दिख रही है। यह बात सही है कि देश का सम्मान करने वाली किसी भी बात पर राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल वोट की चाहत के चलते ऐसा करना और भी खतरनाक हो जाता है।

वन्दे मातरम् भारत की स्वतंत्रता चेतना, मातृभूमि के प्रति समर्पण और राष्ट्रीय स्वाभिमान का ऐसा उद्घोष है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में असंख्य भारतीयों के भीतर देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित की। यही कारण है कि आज जब वन्दे मातरम् के पूर्ण या आंशिक गायन को लेकर राजनीतिक बहस खड़ी होती है, तो प्रश्न केवल गीत की पंक्तियों का नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक दृष्टिकोण का भी बन जाता है।

आज सवाल यह है कि वन्दे मातरम् पर संग्राम क्यों ? कांग्रेस की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि 1937 में इसके दो पदों के गायन को लेकर निर्णय हुआ था, इसलिए उसी परंपरा का पालन होना चाहिए। लेकिन 1937 की परिस्थितियों को 2026 के भारत पर उसी रूप में लागू करना कितना उचित है, इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। 1937 में भारत स्वतंत्र नहीं था। अंग्रेजी शासन था, साम्प्रदायिक तनाव थे और देश की राजनीतिक परिस्थितियां अत्यंत जटिल थीं। कांग्रेस उस समय आज की तरह सत्ता प्राप्त करने वाला चुनावी राजनीतिक दल नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख राजनीतिक मंच थी। जिसमें सभी देश भक्त शामिल थे। आज की कांग्रेस उससे अलग है। वन्दे मातरम् को लेकर कांग्रेस के भीतर भी यह चर्चा हुई कि इसके कुछ अंशों को लेकर मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग की आपत्तियों को कैसे देखा जाए। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि कांग्रेस कार्यसमिति ने 1937 में इस विषय पर विचार किया था और सार्वजनिक अवसरों पर पहले दो पदों के प्रयोग की व्यवस्था बनी। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या उस समय की राजनीतिक परिस्थिति आज के स्वतंत्र भारत के लिए भी अंतिम मानक होनी चाहिए?

भारत आज एक संप्रभु गणराज्य है। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को वन्दे मातरम् के ऐतिहासिक महत्व



को स्वीकार करते हुए इसे राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समान सम्मान देने की व्यवस्था की थी। वन्दे मातरम् को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। इसलिए इसे केवल कांग्रेस, भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक दल के चरम से देखना उचित नहीं है। यहां यह सवाल भी उठता है कि जब यह राष्ट्र गीत है, तब इसे लेकर अपराष्ट्रीय कार्य करने की राजनीति क्यों की जा रही है। यह आत्म मंथन का विषय हो सकता है।

यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट करना भी आवश्यक है। वन्दे मातरम् संविधान के मूल पाठ में लिखकर नागरिकों के लिए अनिवार्य गायन के रूप में शामिल नहीं था। लेकिन चूँकि वन्देमातरम गाने को लेकर कानून बन गया है, तब सभी को इसका पालन करना ही चाहिए, कांग्रेस को भी। आज अगर कांग्रेस इसका विरोध करती है, तो इसे संविधान का अपमान ही कहा जाना उचित होगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और इसके पूर्ण छह अंतरे वाले संस्करण को सार्वजनिक प्रसारण में बढ़ावा दिया गया है। जुलाई 2026 में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कानून में संशोधन का प्रस्ताव भी लाया गया, जिसमें राष्ट्रीय गीत को जानबूझकर रोकने या उसके गायन में व्यवधान डालने के विरुद्ध कानूनी संरक्षण देने की बात है। इसलिए बहस को तथ्यों के आधार पर ही आगे बढ़ाना चाहिए।

वन्दे मातरम् की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी पहचान किसी एक राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी। कांग्रेस के अधिवेशनों में इसका गायन हुआ। 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इसे गाया था। स्वतंत्रता आंदोलन में यह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना। ऐसे में यह कहना कि वन्दे मातरम् भाजपा की देन है, इतिहास के साथ अन्याय होगा। भाजपा तो स्वतंत्रता के बाद बनी; वन्दे मातरम् उससे बहुत पहले भारतीय राष्ट्रचेतना का हिस्सा बन चुका था। फिर वही प्रश्न उठता है कि आज इसके दो पदों या पूरे गीत को लेकर इतना राजनीतिक संघर्ष क्यों? क्या इसके पीछे वोट बैंक

की राजनीति है? इस प्रश्न का उत्तर किसी एक दल के बारे में निश्चित रूप से देना उचित नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक मंशा का प्रमाण तथ्यों से ही स्थापित किया जा सकता है। लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जब राष्ट्रीय प्रतीकों को बार-बार चुनावी गणित से जोड़ दिया जाता है, तब राष्ट्रहित पीछे और राजनीतिक हित आगे दिखाई देने लगता है। वन्दे मातरम् का सम्मान करना किसी धर्म विशेष का समर्थन करना नहीं है। यह मातृभूमि के प्रति सम्मान और स्वतंत्रता संघर्ष की स्मृति से जुड़ा राष्ट्रीय भाव है।

भारत की शक्ति ही उसकी विविधता है। यहां पूजा-पद्धतियां अलग हो सकती हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, पर मातृभूमि के प्रति सम्मान का भाव साझा हो सकता है। इसलिए वन्दे मातरम् को हिन्दू बनाम मुस्लिम विवाद में बदल देना उसके ऐतिहासिक और राष्ट्रीय स्वरूप को छेड़ा करना है।

कांग्रेस के लिए भी यह आत्ममंथन का समय है। यदि 1937 के निर्णय को आज भी राजनीतिक ढाल बनाया जाएगा, तो यह प्रश्न उठेगा कि क्या स्वतंत्र भारत की परिस्थितियों में भी वही दृष्टिकोण अपरिवर्तित रहना चाहिए? और यदि कांग्रेस स्वयं वन्दे मातरम् के इतिहास की भागीदार रही है, तो उसे इस गीत को लेकर अस्पष्टता के बजाय स्पष्ट राष्ट्रीय दृष्टिकोण सामने रखना चाहिए। इसी प्रकार सत्ता पक्ष को भी यह ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रभक्ति किसी पर थोपी जाने वाली भावना नहीं है। राष्ट्रगीत का सम्मान बढ़े, उसके इतिहास को नई पीढ़ी जाने और उसके प्रति स्वाभाविक श्रद्धा विकसित हो, यह अधिक स्थायी रास्ता है। कानून और राजनीतिक आह्वान अपनी जगह हैं, लेकिन राष्ट्रभाव अंततः मन से पैदा होता है।

वन्दे मातरम् को राजनीति के अखाड़े से निकालकर राष्ट्रचेतना के केंद्र में स्थापित करने की आवश्यकता है। इसे कांग्रेस बनाम भाजपा का विषय बनाना भी गलत है और हिन्दू बनाम मुस्लिम का विषय बनाना भी। यह भारत की स्वतंत्रता यात्रा का अमूल्य अध्याय है। कांग्रेस को अपने राजनीतिक उत्थान से आगे बढ़कर देश के उत्थान के बारे में सोचना चाहिए। वन्दे मातरम् किसी दल की संपत्ति नहीं, भारत की राष्ट्रीय विरासत है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पूछें जब इसके शब्दों में मातृभूमि के प्रति वंदन है, इसके इतिहास में स्वतंत्रता का संघर्ष है और इसकी स्मृति में असंख्य देशभक्तों का त्याग है, तब इसे विवाद का नहीं, संवाद का विषय बनाया जाना चाहिए। राजनीति अपनी जगह रहे, लेकिन राष्ट्र सबसे ऊपर रहे।

2029 से ही ‘एक देश, एक चुनाव’ को लागू करने की तैयारी तेज !

नीरज कुमार दुबे

भले ही देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए अपनी-अपनी बिसात बिछाने में जुटी हों, लेकिन भारतीय राजनीति की इस शतरंज पर जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और बड़ा ‘मास्टरस्ट्रोक’ चलने की संभावना जोर पकड़ रही है। हम आपको बता दें कि ‘एक देश, एक चुनाव’ का विचार अब महज बहस या चुनावी नारा नहीं रह गया है, भारत इसके क्रियान्वयन से कुछ ही कदम दूर दिखाई दे रहा है। वगों और भाजपा देशभर में विभिन्न सामाजिक और पेशेवर वर्गों के बीच इस विचार के समर्थन में अभियान चलाकर जनमत तैयार करने में जुटी है, वहीं इस मुद्दे पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति भी राज्यों, विधायिकाओं, शिक्षाविदों, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से व्यापक चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के चरण में पहुंच रही है। ऐसे में सियासी हलकों में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या चुनावी राजनीति की मौजूदा बिसात बदलने वाली है और क्या ‘एक देश, एक चुनाव’ मोदी सरकार की अगली बड़ी राजनीतिक चाल साबित होगी।

हम आपको बता दें कि मौजूदा विधेयकों की मूल रूपरेखा के अनुसार देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक चक्र में लाने की पहली वास्तविक संभावना 2034 से बनती है। संसद की संयुक्त समिति संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की जांच कर रही है। इन प्रावधानों का उद्देश्य अगले चुनाव चक्र में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ लाना है। लेकिन राजनीतिक सत्ता का गणित शायद अब 2034 तक इंतजार करने के मूड में नहीं है।

एनडीए के शासन वाले 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 11 में अगले दो वर्षों के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं। यदि इन राज्यों में एनडीए अपनी सरकारें



बरकरार रखता है, तो 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ इन्हें चुनावी चक्र में लाने के लिए जनवरी 2029 तक विधानसभाएं भंग करने का विकल्प सामने आ सकता है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में विधानसभा चुनाव पहले से ही लोकसभा चुनाव के साथ होते रहे हैं। इस प्रकार इन चार राज्यों को समन्वित चुनावी चक्र में लाना अपेक्षाकृत आसान होगा।

इसके अलावा, संवैधानिक रास्ता भी राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। संविधान का अनुच्छेद 174(2)(b) राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार देता है, हालांकि सामान्य परिस्थितियों में यह फैसला मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। विधानसभा भंग होने के बाद जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत निर्धारित समय सीमा में चुनाव कराना आवश्यक होता है। यही वह संवैधानिक खिड़की है, जिसके जरिए 2029 के साथ चुनावों का समन्वय करने की राजनीतिक संभावना तलाशी जा रही है।

यहीं से ‘एक देश, एक चुनाव’ का प्रशासनिक तर्क सीधे राजनीतिक रणनीति में बदल जाता है। सवाल यह है कि क्या किसी निर्वाचित विधानसभा का कार्यकाल तीन या चार वर्ष तक घटकर चुनावी चक्र को एक साथ लाना मुहज चुनाव सुधार होगा, या फिर यह सत्ता की सुविधानुसार राजनीतिक कैलेंडर को पुनर्गठित करने की शुरुआत होगी? एनडीए के लिए यह योजना चुनावी संसाधनों, संगठनात्मक ताकत और राष्ट्रीय नेतृत्व की लोकप्रियता को एक साथ मैदान में उतारने का अवसर बन

सकती है। एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने पर राष्ट्रीय मुद्दों की लहर राज्य-स्तरीय समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक दृष्टि से यह विषय के लिए बड़ी चुनौती होगी। पंजाब में 2027 और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम तथा तेलंगाना में 2028 में चुनाव प्रस्तावित हैं। इनके बाद चुनी जाने वाली विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 के लोकसभा चुनाव तक केवल एक या दो वर्ष पुराना होगा, जबकि यदि भविष्य में उन्हें लोकसभा चुनाव के चक्र से जोड़ा जाता है तो उनकी अवधि को लेकर अलग संवैधानिक और राजनीतिक बहस खड़ी होगी। दूसरी ओर, 2028 में मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और त्रिपुरा जैसे राज्यों के चुनाव तथा 2029 के आसपास विभिन्न राज्यों के अलग-अलग चुनावी कार्यक्रम देश के मौजूदा बिखरे हुए चुनाव चक्र की जटिलता को दिखाते हैं।

संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी ने इस संभावना पर साफ कहा है कि 2029 में चुनावों को आगे बढ़ाकर एक साथ कराने का फैसला समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यह संबंधित एनडीए मुख्यांत्रियों पर निर्भर करेगा। हम आपको याद दिला दें कि यह समिति दिसंबर 2024 में गठित हुई थी और राज्यों में सरकारें, विधायिकाओं, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से संवाद कर रही है। उसकी रिपोर्ट इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र में आने की उम्मीद है।

लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर विषय पहले ही अपनी तलवारें खींच चुका है। कांग्रेस का तर्क है कि ‘एक देश, एक चुनाव’ असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और जवाबदेही की भावना के विरुद्ध है। विपक्ष का सवाल यह भी है कि यदि विधानसभा का जनादेश पांच वर्ष के लिए है, तो उसे राजनीतिक सुविधा के लिए बीच में समाप्त करना मतदाता के अधिकारों और संघीय ढांचे के साथ किस हद तक न्याय करेगा। यह विवाद उस समय और तीखा हो सकता है, जब परिसौमन को लेकर केंद्र और विपक्षी दलों के बीच पहले से ही अविश्वास मौजूद है।

ई-20 पेट्रोल : ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ उपभोक्ताओं का विश्वास भी जरूरी

देवेश त्रिपाठी

देश में पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिश्रण को लेकर मिल रही उपभोक्ताओं की शिकायतों के बीच ऑटोमोबाइल कंपनियों और विशेषज्ञों ने सरकार द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों की चिंताएं दूर करने की जो कोशिश की, वह जरूरी भी थी, क्योंकि ई-20 पेट्रोल को लेकर सभी संदेहों को दूर होना ही चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि ई-20 पेट्रोल से इंजन की कार्यक्षमता, माइलेज और पुराने वाहनों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर उठ रहे सवाल लगातार बहस का विषय बने हुए हैं। अब तो सरकार, कंपनियों और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि इस ईंधन के उपयोग से वाहनों का माइलेज दो से छह फीसदी तक कम हो सकता है। दरअसल, ई-20 पेट्रोल को लागू करने के पीछे सरकार के कई उद्देश्य हैं, मसलन, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा की उपलब्ध कराना। इन उद्देश्यों पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देश के लिए वैकल्पिक ईंधन की ओर बढ़ना समय की मांग भी है। लेकिन किसी भी नई व्यवस्था की कामयाबी केवल सरकार की सख्तिख से नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे से भी तय होती है। व्यावहारिक ढंग से देखें, तो उपभोक्ता सिर्फ पर्यावरणीय या राष्ट्रीय फायदे के लिए कोई नई व्यवस्था नहीं स्वीकारता। वह अपनी जेब, वाहन की सुरक्षा और भविष्य की लागत को भी देखता है। वाहन निर्माता कंपनियां यह दावा कर



रही हैं कि नए मॉडल ई-20 के अनुरूप हैं, लेकिन देश में करोड़ों ऐसे दो और चार पहिया वाहन हैं, जिन्हें खासकर ई-20 ईंधन के लिए तैयार नहीं किया गया है। सोशल मीडिया ने इस संशय को और बढ़ाया है। ई-20 से इंजन खराब होने या माइलेज में भारी गिरावट के वायरल हो रहे कई वीडियो अतिरंजित या अपुष्ट हो सकते हैं, लेकिन जब आधिकारिक स्तर पर समय रहते वैज्ञानिक और तकनीकी तथ्यों के साथ उनका जवाब नहीं दिया जाता, तब अफवाहों भी सच का रूप लेने लगती हैं। अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, जापान, थाईलैंड और कई यूरोपीय देशों में ई-20 पेट्रोल का उपयोग तो हो ही रहा है। ऐसे में, अगर ई-20 पेट्रोल में वाकई कोई गंभीर तकनीकी समस्या नहीं है, तो विरोध में हो रहे प्रचार अभियान का पूरी पारदर्शिता के साथ व्यवस्थित प्रतिकार होना चाहिए। और अगर कहीं कुछ चुनौतियां हैं, तो उन्हें स्वीकार कर समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। जनता का भरोसा संवाद और जवाबदेही से बनता है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते देश के लिए यह भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होगा।



आलिंगन सिर्फ अंतरंगता के लिए ही नहीं होता है, बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा होता है। आलिंगन प्यार जताने का एक बेहतरीन तरीका तो है ही साथ ही इसके स्वास्थ्यगत फायदे भी हैं। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और तनाव कम होता है। वैज्ञानिकों को पता चला है कि जब आप किसी को गले लगाते हैं, तो इससे रक्त में एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन का साव होता है। इससे उच्च रक्तचाप में कमी आती है, तनाव और बेचैनी कम होती है और इससे आपकी स्मरण शक्ति भी बेहतर होती है।

किताबें पढ़ने वाले ज्यादा जीते हैं ...



कुछ लोग अधिक पढ़ने वाले लोगों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें किताबी कीड़ा तक कहते हैं। अब एक रिसर्च में पता चला है कि जो लोग किताबें अधिक पढ़ते हैं, वे दूसरों की तुलना में अधिक दिनों तक जीते हैं। यह रिसर्च अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी में किया गया है। इस रिसर्च में 50 वर्ष से अधिक उम्र के 3635 लोगों को शामिल किया गया। इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों को तीन ग्रुप में बांट दिया गया। पहले ग्रुप में किताब नहीं पढ़ने वाले लोगों को शामिल किया गया। दूसरे ग्रुप में साढ़े तीन घंटे तक किताब पढ़ने वाले लोगों को शामिल किया गया और तीसरे ग्रुप में साढ़े तीन घंटे से अधिक पढ़ने वाले लोगों को शामिल किया गया। रिसर्च में पाया गया कि अधिक पढ़ने वाले लोगों में अधिकतर लड़कियां, कॉलेज कर चुके लोग और अधिक आय वाले लोग थे। रिसर्च में देखा गया कि साढ़े तीन घंटे तक पढ़ने वाले लोगों में सही पढ़ने वाले लोगों की तुलना में 12 वर्ष के अंतराल में 17 प्रतिशत कम लोगों की मृत्यु हुई। जो लोग साढ़े तीन घंटे से अधिक पढ़ रहे थे, उनमें मृत्यु दर 27 प्रतिशत तक कम देखी गई। किताब पढ़नेवाले औसतन सभी लोग नहीं पढ़ने वालों की तुलना में दो साल अधिक जिए।

रूटीन बिगड़ा तो बिगड़ेंगे बच्चे...



शायी-ब्याह तो कभी छुड़ियों का मौसम। कभी घर पर मेहमान आए, कभी खुद कहीं चले गए। इस आपाधापी में आपका रूटीन तो खराब होता ही है, बच्चों का रूटीन भी गड़बड़ा जाता है। उनका रूटीन वैसा नहीं रह पाता, जैसा सामान्य दिनों में होता है और यही बात खतरनाक है। बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चों के रूटीन को गड़बड़ाने नहीं देना चाहिए। इन विशेषज्ञों की राय है कि कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे बीमारी, यात्रा आदि को छोड़कर बच्चों के रूटीन को बिगाड़ें नहीं। रूटीन बदलने से बच्चे पढ़ाई से संबंधित कार्य को बोझ समझने लगते हैं। इसलिए माता-पिता को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के सुबह उठने के समय, नहाने, नाश्ता करने, खेलने, टीवी देखने और पढ़ने के समय में विशेष बदलाव नहीं करना चाहिए। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ऐसे सख्त नियम भी न बना डालें कि बच्चों का बचपना ही खत्म हो जाए। कुछ दिन घूमने-फिरने गए हों तो उन्हें पूरी मस्ती करने देना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हो सकता है कि बच्चे कुछ कामों में लेट-लैठीकी करें, लेकिन पूरी तरह रूटीन बदलने पर दिक्कत हो सकती है।

शहरी बच्चे ज्यादा नेगेटिव!



इलाहाबाद में रियत मनोविज्ञानशाला में हाल ही में एक सर्वे हुआ था। ग्रामीण व शहरी इलाकों में छात्र-छात्राओं के बीच करार गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में शहरी बच्चे अपने माता-पिता की उदासीनता के शिकार हो रहे हैं। शोध में यह भी पता चला है कि ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहर के बच्चों पर पारिवारिक उदासीनता का ज्यादा नकारात्मक असर पड़ रहा है। 2015-16 शैक्षिक सत्र में कुल 500 छात्र व 258 छात्राओं पर सर्वे किया गया। ये सभी बच्चे 10वीं के विद्यार्थी हैं। जब लड़के व लड़कियों पर अलग-अलग अध्ययन किया गया तो पता चला कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की शैक्षिक उपलब्धि और समायोजन पर इस उदासीनता का अधिक प्रतिकूल प्रभाव है। सर्वे के बाद अभिभावकों के लिए तीन प्रमुख सुझाव दिए गए हैं। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि दूसरे बच्चों से तुलना की बजाय अपने बच्चे की उपलब्धि एवं अच्छे प्रयासों की सराहना करें। बच्चों पर विश्वास करने की आदत विकसित करें और उन्हें घरेलू कार्य का दायित्व सौंपें जिससे वे शैक्षिक व घरेलू कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम हो सकें। मन की एकाग्रता व रिसरत को बढ़ाने के लिए रोज लगभग 20 मिनट योगाभ्यास करने की सलाह दी गई है।



की

आलिंगन से एक व्यक्ति की आत्मिक ऊर्जा दूसरे के मन और चेतना में प्रवेश करने लगती है। ऐसा करने से परेशान करने को राहत मिलती है। एक अध्ययन से पता चला है कि ब्रिटेनवासी प्रत्येक आलिंगन में नौ सेकेंड से अधिक का समय लगाते हैं और इस तरह हर महीने आलिंगन के लिए वे एक घंटा समय खर्च करते हैं।

सिर्फ यही नहीं, आलिंगन में इतना समय खर्च करने के बावजूद सर्वेक्षण में शामिल किए गए 41 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हम आलिंगन में और भी समय खर्च करना चाहते हैं। सर्वेक्षण में पाया गया है कि 69 प्रतिशत ब्रिटिश अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ आलिंगन करना चाहते हैं, जबकि 14 प्रतिशत अपने करीबी मित्र के साथ और नौ प्रतिशत ही अपनी मां के साथ आलिंगन करना चाहते हैं।

वास्तव में आलिंगन प्यार जताने का सबसे बेहतरीन तरीका है। कोई कितना भी परेशान क्यों न हो किसी अपने के गले लगकर बहुत अच्छा महसूस करता है। क्योंकि आलिंगन से एक व्यक्ति की आत्मिक ऊर्जा दूसरे के मन और चेतना में प्रवेश करने लगती है। ऐसा करने से परेशान व्यक्ति को तो राहत मिलती ही है, साथ ही आलिंगन वाला स्वयं भी ऊर्जा से भर उठता है।

प्यार जताने का तरीका

आलिंगन प्यार जताने का सबसे बेहतरीन तरीका है। कोई कितना भी परेशान क्यों न हो किसी अपने के गले लगकर बहुत अच्छा महसूस करता है। क्योंकि आलिंगन से एक व्यक्ति की आत्मिक ऊर्जा दूसरे के मन और चेतना में प्रवेश करने लगती है। ऐसा करने से परेशान व्यक्ति को तो राहत मिलती ही है, साथ ही आलिंगन वाला स्वयं भी ऊर्जा से भर उठता है। एक ताजा अध्ययन के अनुसार, आलिंगन से स्वास्थ्य को भी फायदा होता है।

ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल

वास्तव में आलिंगन स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और एक स्वस्थ

जीवनशैली को बनाए रखने में भी मदद करता है। यह अवसाद का कम करता है और रक्त के दबाव को बनाए रखने में मदद करता है। रक्तचाप के स्थिर रहने से सिर दर्द और अन्य बीमारियों के होने की आशंका कम होती है।

सिर्फ अंतरंगता नहीं

आलिंगन सिर्फ अंतरंगता के लिए ही नहीं होता है, बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा होता है। जो जोड़े एक-दूसरे को गले लगाते हैं उनका अन्य (जो एक दूसरे को गले नहीं लगाते) जोड़ों की तुलना में मजबूत सम्पर्क होता है। जब कोई अपने पार्टनर को गले लगाता है तो वह भी नहीं जानता कि वह बातचीत के कौन से स्तर पर होता है। यहां तक कि कई बार बिना बोले सिर्फ गले लगाता ही रिश्ते में जादुई असर करता है।

सावधानी भी जरूरी

खिया विश्वविद्यालय के शोध के मुताबिक किसी को गले लगाते वक्त हालांकि सावधानी बरतनी चाहिए। आप उसी को गले लगाएं, जिसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वरना इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि ऑक्सीटोसिन को माता-पिता, बच्चों और दम्पतियों के बीच आपसी प्यार बढ़ाने के लिए प्रमुख कारक माना जाता है। सक्रिय सम्बंध में रह रहे साथियों के बीच ऑक्सीटोसिन का स्तर अधिक पाया जाता है।



डिप्रेशन कम करता है

कई शोधों से भी यह बात साबित हो गई है कि किसी के साथ आलिंगन करने से अवसाद से लड़ने में मदद मिलती है। आलिंगन के दौरान रक्त से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का साव अवसाद से लड़ता है। अगर कोई अपने साथी की बाहों में सोता है तो न केवल उसको आरामदायक और शान्तिपूर्ण नींद आती है बल्कि अगले दिन चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर जागता है।



एक-दूसरे को जानना जरूरी

न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक गले लगाने का फायदा हालांकि तभी मिलता है, जब गले लगने वाले दोनों व्यक्ति एक-दूसरे को जानते हों और एक-दूसरे पर भरोसा करते हों। यदि गले लगने वाले व्यक्ति एक-दूसरे को नहीं जानते या दोनों में से एक गले नहीं लगना चाहे तो इसका कोई फायदा नहीं मिल पाता है। उल्टे इससे बेचैनी बढ़ जाती है। गले लगाना अच्छी बात है, लेकिन भले ही कोई भी कितना भी एक-दूसरे से गले लगे, वास्तविकता यह है कि महत्वपूर्ण चीज आपसी भरोसा है।



रुखापन खत्म होता है

महिलाओं में बच्चों को जन्म देते वक्त और स्तनपान कराते वक्त इस हार्मोन का साव होता है, जिससे माता और बच्चों के बीच लगाव बढ़ता है। शोधार्थियों के मुताबिक अपने प्रियजनों को गले लगाने वाले व्यक्ति के स्वभाव का रुखापन भी समाप्त होता है और उसमें समय के साथ मधुरता का विकास होता है।

इंडियन लाइसेंस से विदेशों में ड्राइविंग...



अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है और कार ड्राइविंग के शौकीन तो आपके लिए यह खुशखबरी है कि आप विदेशों की स्मृथ सड़कों पर भी ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। विदेशों में भी आप इंडियन लाइसेंस को साथ वहां के नियम और कानून का पालन करते हुए कार या फिर बाइक आदि ड्राइव कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां इंडियन लाइसेंस के साथ ड्राइविंग की जा सकती है।

न्यूजीलैंड

अगर आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा है तो आप 1 साल तक न्यूजीलैंड में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कार ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस ड्रैलश में नहीं है तो एबेसी से न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी से ट्रांसलेट कराना होता है।

ऑस्ट्रेलिया

आप न्यू साउथ वेल्स, क्वीन्सलैंड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल टेरिटरी में ही भारतीय वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस से ड्राइव कर सकते हैं। लीगल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप वही गाड़ी चला सकते हैं जिसकी इजाजत भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस में है। यहां इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 3 महीने के तक ही चलेगा।

फ्रांस

फ्रांस में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को एबेसी से फ्रेंच में ट्रांसलेट कराना भूलने पर मुसीबत खड़ी हो सकती है। फ्रांस में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल तक चलता है।

अमेरिका

अमेरिका में आप भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से एक साल तक कार ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाना पड़ेगा।

साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका में कार ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में होना चाहिए और साथ ही इसमें आपको फोटो और साइन होना सबसे जरूरी है।

नार्वे

अगर आपको नार्वे में ज्यादा समय के लिए रहना है तो आपको वहां का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। यहां पर आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 3 महीने तक ही कार ड्राइव कर सकते हैं।

स्विट्जरलैंड

कार ड्राइव करने के लिए इंडियन लाइसेंस स्विट्जरलैंड में सिर्फ 1 साल तक के लिए ही लागल होता है।

इंग्लैंड

इंग्लैंड में आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सिर्फ छोटी कार और बाइक ही अपने लाइसेंस से चला सकते हैं। यूके को कार ड्राइव के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है।

जर्मनी

अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो एबेसी से इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को जर्मनी में ट्रांसलेट करवा सकते हैं और जर्मनी में 6 महीने तक कार ड्राइव कर सकते हैं।



यह अफवाह है

आम तौर पर लोगों में ये भ्रांतियां होती हैं कि विदेश से यदि सोने के आभूषण खरीद कर ला रहे हैं तो उन्हें पहन कर आना चाहिए क्योंकि पहने हुए आभूषणों पर किसी तरह की ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है लेकिन ये सच नहीं है। यहां भी वही नियम और शर्त लागू रहती है।

जाते वक्त भी दें व्योरा

आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विदेश जाने से पहले आपको अपने गहनों के संबंध में करस्टम को जानकारी दे देनी चाहिए। चाहे आपने छोटी सी अंगूठी ही क्यों ना पहनी हो, विदेश जाने से पहले आपको एयरपोर्ट पर ये सुनिश्चित करना होगा कि यह आभूषण आपका है और आप इसे देश से ही पहन कर जा रहे हैं। इससे आप वापसी के दौरान होने वाली परेशानी से बच सकते हैं।

भारत में भी खरा सोना

अब दौर पहले के जैसा नहीं रहा। पहले देश में ये धारणा थी कि यहां मिलने वाला सोना उतना खरा नहीं जितना विदेशी सोना होता है। लेकिन सरकार के नियम अब कड़ाई से लागू किए जा रहे हैं जिससे बाजार में सिर्फ हॉलमार्क के ही सोने के आभूषण बिक रहे हैं। इसलिए अब इस बात से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि देश में मिलने वाला सोना खरा है या नहीं।

विदेश से कितना सोना ला सकते हैं आप?

सोना यानी कि गोल्ड से भारतीयों को कितना लगाव है यह बात किसी से छिपी नहीं है। भारतीयों के गोल्ड प्रेम से दुनिया वाकिफ है। देश में लोग सोने के आभूषण पहनने के अलावा चढ़ावे में भी चढ़ा देते हैं, दान कर देते हैं। विदेशों में रह चुके हैं तो आप 50 हजार रुपए तक का सोना भारत में ड्यूटी फ्री लेकर आ सकते हैं। वहीं महिलाओं के लिए यह छूट एक लाख रुपए तक है। महिलाएं एक लाख रुपए तक की कीमत का सोना खरीद कर ला सकती हैं।



ड्यूटी फ्री सोने की सीमा

ड्यूटी फ्री सोना लाने के लिए आपको कुछ जरूरी बातों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एक वर्ष से अधिक विदेश में रह चुके हैं तो आप 50 हजार रुपए तक का सोना भारत में ड्यूटी फ्री लेकर आ सकते हैं। वहीं महिलाओं के लिए यह छूट एक लाख रुपए तक है। महिलाएं एक लाख रुपए तक की कीमत का सोना ड्यूटी फ्री लेकर भारत आ सकती हैं।

सिक्के और बिस्किट

अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो क्या विदेश से सोने के सिक्के या फिर सोने के बिस्किट ड्यूटी फ्री शर्तों के अंतर्गत लेकर आ सकते हैं ? इसका जवाब है नहीं। क्योंकि ड्यूटी फ्री की शर्तें सिर्फ सोने के आभूषणों पर लागू हैं और उनकी भी सीमा है ऐसे में आपको सोने के सिक्कों और बिस्किट्स पर ड्यूटी देना पड़ेगा।

कितना है ड्यूटी शुल्क

एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि, अगर सोना निर्धारित कीमत से अधिक है तो कितनी ड्यूटी चुकानी होगी? तो इसका जवाब है कि आपके पास ड्यूटी फ्री सोने से जितना अधिक सोना है उसका 10.3 प्रतिशत आपको चुकाना होगा। इस मामले में भी आपको नियम और शर्तें जान लेनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति एक किलो से अधिक सोना नहीं ला सकता।

रसीद साथ रखिए

आप यदि विदेश से सोने के आभूषण या फिर सिक्के खरीदकर ला रहे हैं तो आपको उसकी रसीद साथ रखनी चाहिए। यह करस्टम में पूछ-ताछ के दौरान आपकी मदद करेगी साथ ही आपके पास खरीदारी और सोने की सही कीमत का एक प्रमाण भी रहेगा। इस तरह की रसीद आपको आगे आने वाली परेशानियों से बचाएगी।

बांके बिहारी के चढ़ावे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त



नईदिल्ली। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मंदिर में दान किया गया एक-एक पैसा दान पात्र यानी गुरुक में जमा चढ़ावा या ऑनलाइन माध्यम से भेजी गई रकम सीधे मंदिर के आधिकारिक खजाने और खाते में ही जानी चाहिए, अदालत ने साफ किया है कि यदि सेवायत या कोई अन्य व्यक्ति इस प्रक्रिया में कोई बाधा खड़ी करता है तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर की प्रबंध समिति को किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का आदेश कोर्ट ने दिया है.कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर के धन का उपयोग करके कोई भी संपत्ति या जमीन खरीदने के किसी भी प्रस्ताव पर अमल करने से पहले उसे अदालत के समक्ष लाना अनिवार्य होगा. याचिकाकर्ता की वकील तन्वी दुबे ने कहा कि हाई पावर कमेटी ने साल भर में 40 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन हालात जस के तस हैं।

संन्यास के संकेत फिर सफाई भी



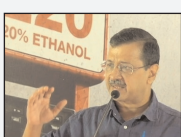
नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान से राजनीतिक हलकों में काफी हलचल मच गई. उन्होंने कहा कि अब वे पहले जितना काम नहीं कर सकते और समय आ गया है कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारियां सौंपी जाएं. नागपुर के एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि हाल-फिलहाल में सार्वजनिक कार्यों में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम हो गई है. उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी को मौका दिया जाए. खास बात यह है कि नितिन गडकरी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केंद्रीय कैबिनेट के फेरबदल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. नितिन गडकरी ने कहा, मैं पिछले 30 सालों से लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ. इस दौरान मैंने कई उतार-चढ़ाव भी देखे, कई बार पुरस्कृत भी हुआ. हालांकि, अब इस पर नितिन गडकरी के कार्यालय की ओर से स्पष्टीकरण आया है और बताया गया है कि उनका यह बयान लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट के संबंध में था।

मनुस्मृति और हिजाब वाले बयान पर घिरी कांग्रेस



नई दिल्ली। राहुल गांधी के मनुस्मृति पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है. बीजेपी ने राहुल के हिजाब समर्थन वाले पुराने वीडियो को शेयर कर उन्हें पाखंडी बताया है.कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मनुस्मृति पर दिए गए बयान को लेकर सियासत जारी है. इस बीच अब बीजेपी ने उनके हिजाब के समर्थन में दिए उनके पुराने बयान का हवाला देते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया है. बीजेपी ने राहुल गांधी पर %पाखंड% का आरोप लगाया है. बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो शेयर किया है. इसमें राहुल से एक इवेंट में एक लड़की के हिजाब पहनने को महिला को आज्ञादी से जोड़ने के मुद्दे पर सवाल करती दिखाई दे रही है.युवती के सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता कहते हैं, मेरी राय है कि जो महिला हिजाब पहनना चाहती है वो उसके ऊपर निर्भर करता है।

गोवा में ई 20 के खिलाफ आप ने खोला मोर्चा



गोवा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गोवा में ई 20 पेट्रोल के खिलाफ दूसरा टाउनहॉल किया. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा. केजरीवाल ने कहा कि इनको लगता है कि जनता वोट तो हमें ही देगी, सरकार तो हमारी ही बनेगी. इनको यह अहंकार है कि जनता हमारे पास ही आएगी, कहा जाएगा. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में एक बार अगर गोवा और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी हार जाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 मार्च को नतीजे आएंगे और 15 मार्च तक ई 20 वापस हो जाएगा. उन्होंने कहा कि गोवा के अंदर 87% लोग ई 20 की वजह से परेशान हैं. 87% लोग टून्लीर ओन करते हैं और 47% लोग फोर-व्हीलर ओन करते हैं. अगर सब मिलकर एक बार ठान लें कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है, तो मुझे लगता है कि 5 दिन के अंदर अगर थ्रु20 वापस नहीं हो जाए, तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा।

भाजपा को हाशिए पर धकेलने तक संन्यास नहीं: ममता



कोलकाता। पश्चिम बंगाल को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक संन्यास को लेकर एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने साफ कहा कि वे जब तक बीजेपी को हाशिए पर नहीं धकेल देती तब तक राजनीति से संन्यास नहीं लेंगी. एक फेसबुक लाइव में ममता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने बीजेपी का असली चेहरा पहचान लिया है. उनका आरोप है कि राज्य में नागरिकों को बड़े पैमाने पर डराया-धमकाया जा रहा है. ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए तल्लख लहजे में कहा, जो लोग सोच रहे हैं कि जगह की अनुमति नहीं मिलने से परेशान होकर मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी, वह किसी गलतफहमी में हैं. ममता का कहना है कि उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक वे बीजेपी को संन्यास लेने पर मजबूर नहीं कर देती. ममता ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर रही है. और एसपी जिला अध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं. 12,000 से 14,000 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह का पी. चिदंबरम पर पलटवार

कांग्रेस ने ही बिगाड़ा ‘एक देश एक चुनाव’ का सिस्टम

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को एक देश, एक चुनाव का विरोध करने वाले कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम पर पलटवार किया। उन्होंने तर्क दिया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव पहले एक साथ ही होते थे, लेकिन तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस ने इस व्यवस्था को बिगाड़ दिया। इससे पहले, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा था कि अगर संसद संपेक देश, एक चुनाव बिल पास भी हो जाए, तो भी 2029 में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं होगा। एक्स पर एक पोस्ट में चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने एक देश, एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सामने अपनी बात रखी थी और कहा था कि यह बिल संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है।



पलटवार करते हुए शिवराज चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने 1970 के दशक में असंवैधानिक तरीकों से विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को गिराया था। पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने पी चिदंबरम का बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने दावा किया है कि एक देश, एक चुनाव असंवैधानिक है और कांग्रेस पार्टी की अंतरात्मा इसे लागू करने की इजाजत नहीं देती। वे किस अंतरात्मा की बात कर रहे हैं? लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव पहले एक साथ ही होते थे; ऐसा 1952, 1957, 1962 और 1967 में हुआ था। बाद में, कांग्रेस पार्टी ने असंवैधानिक तरीकों से विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को गिराने की साजिश रची और इस व्यवस्था को बिगाड़ दिया।

एक देश, एक चुनाव के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए चौहान ने कहा कि लॉ कमीशन ने कई बार और पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई-लेवल कमेटी ने एक साथ चुनाव कराने

की बात कही है। उन्होंने कहा कि 1983 में लॉ कमीशन ने कहा था कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना जरूरी है। चुनाव आयोग की भी यही राय थी। लॉ कमीशन ने 2018 में फिर से यही बात दोहराई। तो फिर यह असंवैधानिक कैसे हो गया? पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अगुवाई वाली कमेटी ने एक देश, एक चुनाव की जरूरत पर रिपोर्ट तैयार करने से पहले देश भर के बुद्धिजीवियों और कानूनी विशेषज्ञों से बातचीत की। इस प्रस्ताव में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने और उसके बाद 100 दिनों के भीतर अन्य चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर में बार-बार होने वाले चुनावों के कारण चुने हुए नेता विकास कार्यों पर समय नहीं दे पाते हैं। इस मामले पर कांग्रेस के रुख को खारिज करते हुए उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर जनता भी एक देश, एक चुनाव चाहती है। उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले चुनावों से न केवल सरकार और राजनीतिक दलों का खर्च बढ़ा है, बल्कि विकास में भी बाधा आई है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी कार्यकर्ता चुनावों में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं। शिक्षक, राजस्व विभाग के कर्मचारी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी – जनसेवा, कल्याण और विकास पर ध्यान देने के बजाय – सिर्फ चुनाव की तैयारियों में ही लगे रहते हैं। आज, यह सबसे जरूरी जरूरत है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी का रुख एक बात है, लेकिन राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है; एक देश, एक चुनाव राष्ट्रीय और जनहित के लिए जरूरी है। मोटे तौर पर, जनता के बीच इस बात पर आम सहमति है कि चुनाव एक साथ होने चाहिए।

खड़गे ने जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना

नईदिल्ली। बुधवार को कांग्रेस ने ज़रूरी चीजों की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर अपना हमला तेज़ कर दिया. पार्टी ने कहा कि बीजेपी के अच्छे दिन के वादे के बजाय, लोगों के घर के बजट पर लगातार बोझ बढ़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ध्यान भटकाने वाले हथकंडों और बेतुकी बातों का सहारा लेकर अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी और जनता महंगाई के मुद्दे पर सवाल उठाना जारी रखेंगे।



रोज़मर्रा की जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि पिछले एक साल में प्याज की कीमतों 59 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं और कई शहरों में यह 50-60 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमत 60-70 रुपये प्रति किलो है और कुछ जगहों पर यह 72 रुपये तक पहुँच गई है, जबकि सरसों का तेल 200 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा में बिक रहा है। खड़गे ने खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर 5.52 प्रतिशत और थोक महंगाई दर 9.78 प्रतिशत होने का भी जिक्र किया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि बढ़ती कीमतों का आम परिवारों पर, खासकर त्योहारों के मौसम में, क्या असर पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के 12 साल हो गए हैं और अच्छे दिन की सच्चाई यह है कि कभी दाल, कभी सब्जी, कभी तेल, तो कभी चीनी आम आदमी का बजट बिगाड़ती रहती है। कांग्रेस ने सोमवार को भी तेज़ी से बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। पार्टी ने पूछा था कि सरकार के अच्छे दिन लाने के दावों के बावजूद गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपना गुज़ारा कैसे करेंगे। विपक्षी पार्टी ने बार-बार मोदी सरकार पर ज़रूरी चीजों की कीमतों को काबू करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि वोटर महंगाई के असर को याद रखेंगे।

मजबूत शुरुआत के बाद फिसला बाजार, निफ्टी 24200 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को फिर से बिकवाली देखने को मिली। सुबह मजबूत शुरुआत के बावजूद बेंचमार्क इंडेक्स अंत में लाल निशान में बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 183 अंक नीचे 77,472 पर बंद हुआ, जो कारोबारी सेशन में 77,986.84 तक उछला। निफ्टी भी दिन के सबसे उच्चतम स्तर 24,378.60 से फिसलकर 24,207.75 पर बंद हुआ है। घरेलू बाजारों में सबसे ज्यादा बिकवाली आईटी समेत सेक्टर में देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1.5 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी 50 में शामिल 50 में से 36 शेयर गिरकर बंद हुए, जिसमें इंफोसिस, भारती एयरटेल, पावरग्रिड के शेयरों में 2-2 फीसदी से ज्यादा की कमजोरी दर्ज की गई। वहीं, कोटक बैंक का शेयर 3.76 फीसदी की तेजी के साथ इंडेक्स का टॉप गेनर रहा।

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को पारेषण परियोजना मिली

नई दिल्ली। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) को महाराष्ट्र में 4,500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा एवं भंडारण बिजली की निकासी के लिए 4,700 करोड़ रुपए की पारेषण परियोजना मिली है। कंपनी के बुधवार को जारी बयान के अनुसार, पश्चिमी क्षेत्र में सातारा के पास पंप स्टोरेज क्षमता के लिए नेटवर्क विस्तार योजना (4,500 मेगावाट तक)– भाग-ए परियोजना (एईएसएल को शुल्क आधारित प्रतियुद्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के जरिये मिली है। बयान के अनुसार, निजी पारेषण एवं वितरण कंपनी और वैश्विक स्तर पर विविधीकृत अडानी समूह का हिस्सा एईएसएल ने कर्नाटक में उत्पन्न होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा को महाराष्ट्र के प्रमुख बिजली खपत केंद्रों तक पहुंचाने के लिए यह महत्वपूर्ण पारेषण परियोजना हासिल की है।

तेल संकट के बीच खींचतान से गुजर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था

वॉशिंगटन। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में अवरोध से उत्पन्न तेल संकट का वैश्विक अर्थव्यवस्था ने विभिन्न कारणों से आशंका से बेहतर सामना किया है। इनमें कुत्रिम मेधा (एआई) में निवेश में तेजी भी शामिल है। जॉर्जीवा ने कहा, एआई की शुरुआत अमेरिका तक सीमित एक घटना थी लेकिन अब यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि का एक प्रमुख शक्ति बन रही है। अन्य देश भी डेटा सेंटर और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी ला रहे हैं। जॉर्जीवा ने अगले सप्ताह उत्तरी कैरोलिना के एशविले में होने वाली जी-20 वित्त मंत्रियों की बैठक से पहले कहा, वहीं, एआई में निवेश में तेजी से इसे बढ़ावा मिल रहा है। खासकर अमेरिका में, जहां कंपनियों की आय और उपभोक्ता मांग दोनों मजबूत बनी हुई हैं।

ईरान पर ट्रंप का आर्थिक शिकंजा, भारत पर बढ़ा संकट

नई दिल्ली। ईरान के खिलाफ अमेरिका के नए ‘ऑपरेशन इकनॉमिक आउटकास्ट’ से भारत के लिए व्यापार, शिपिंग और ऊर्जा क्षेत्र में जोखिम बढ़ने की आशंका है। करीब छह महीने के सैन्य संघर्ष के बाद भी निर्णायक नतीजा नहीं निकलने पर ट्रंप प्रशासन अब ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए वित्तीय और व्यापारिक दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसंट ने देशों को ईरान के साथ कारोबार सीमित करने की चेतावनी देते हुए आने वाले दिनों में नए प्रतिबंधों के संकेत दिए हैं। भारत पर इसका सीधा असर बासमती चावल के निर्यात पर पड़ सकता है। भारत हर साल करीब 50-60 लाख टन बासमती चावल निर्यात करता है, जिसमें लगभग 10 लाख टन ईरान जाता है।

दुनियाँ में आर्थिक तूफान, भारत की नई उड़ान

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर भारत जब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, तब दुनियाँ की अर्थव्यवस्था एक बिल्कुल अलग प्रकार के अंतरिक्ष, भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता,में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका-ईरान तनाव,होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ती टकरावपूर्ण बयानबाजी महंगा कच्चा तेल,ऊंची वैश्विक बॉन्ड यील्ड और टैरिफ युद्ध है; दूसरी ओर भारत अंतरिक्ष स्टार्टअप,जापान के साथ निवेश,एफडीआई सुधार, तकनीकी साझेदारी और बहुस्तरीय रणनीतिक कूटनीति के माध्यम से भविष्य की आर्थिक नींव मजबूत करने में लगा है।यही वास्तुधाभास आज भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कानजी है बाहर तूफान है लेकिन भीतर भारत अपनी आर्थिक नाव को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। में यह बताना चाहूंगा कि

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस दिनांक 23 अगस्त 2026 को मनाया गया परंतु इसके पूर्व पीएम ने 21 अगस्त को नई दिल्ली में 20 भारतीय स्पेस-टेक स्टार्टअप्स के संस्थापकों और सीईओ से संवाद किया। इस बैठक की बातचीत और मुख्य अंशों का टीवी व सोशल मीडिया पर आधिकारिक प्रसारण 23 अगस्त को सुबह 10 बजे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किया गया, इसमें कार्सरूट एयरोस्पेस अिनकूल कासर्मास पिक्सेल, ध्रुव स्पेस, दिगंतरा सहित अनेक कंपनियां शामिल थीं।पीएम ने अंतरिक्ष तकनीक को केवल रॉकेट और उपग्रहों तक सीमित न रखते हुए कृषि, पशुपालन,डैयरी,पर्यावरण और आम नागरिकों के दैनिक जीवन से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता बताई जिसमें दुनियाँ जबअंतरिक्ष की ओर देखे तो भारत दिखाई दे और वैश्विक प्रतिभा,कंपनियां तथा निवेश



भारत की ओर आकर्षित हों। मेरे विचार से यह घटनाक्रम केवल विज्ञान एवं तकनीक के खबर नहीं है, बल्कि भारत की नई अर्थव्यवस्था का संकेत है।अंतरिक्ष आधारित पृथ्वी अवलोकन से किसानों को मौसम, फसल, मिट्टी और जल-संसाधनों की बेहतर जानकारी मिल सकती है; सैटेलाइट डेटा पर्यावरण नियंत्रण,आपदा प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर नियोजन में उपयोगी हो सकता है। भारत में 2014 में केवल एक पंजीकृत स्पेस स्टार्टअप से संख्या 2026 में 400 से अधिक हो चुकी है।इसका अर्थ है कि अंतरिक्ष अब केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि

निजी पूंजी, स्टार्टअप रोजगार,निर्यात और उच्च तकनीक आधारित औद्योगिक विकास का नया क्षेत्र बन रहा है।इसी बीच भारत की दूसरी बड़ी आर्थिक पहल जापान के साथ दिखाई देती है। साथियों, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री 24 से 27 अगस्त 2026 तक जापान की यात्रा पर हैं और भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। 200 से अधिक भारतीय कारोबारी प्रतिनिधियों वाला यह दल टोक्यो, नागोया और ओसाका में जापानी उद्योग जगत के साथ व्यापार और निवेश के अवसर तलाश रहा है। सेमोकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, स्टील, विनिर्माण वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में सहयोग इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत-जापान संबंधों का आर्थिक महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं चीन-केंद्रित मॉडल

से विविधीकरण की ओर बढ़ रही हैं। जापान की पूंजी,तकनीक और औद्योगिक विशेषज्ञता तथा भारत का विशाल बाजार, युवा मानव संसाधन और डिजिटल इकोसिस्टम मिलकर विनिर्माण एवं तकनीकी निवेश की नई संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। अंदरू दशक में जापानी निवेश के लिए 10 ट्रिलियन येन के लक्ष्य को गति देना केवल विदेशी पूंजी जुटाने का प्रयास नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक उत्पादन नेटवर्क का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की सटीकता से रणनीति है। साथियों, इसके पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में चौथे भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलेमेज सम्मेलन 19 से 20 अगस्त 2026 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही थीं, विदेश मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्यमंत्री की सिंगापुर यात्रा का परिणाम केवल उच्चस्तरीय बैठकों के तक सीमित नहीं रहा।



छत्तीसगढ़ शासन

महतारी गौरव वर्ष 2026

महिला स्वाभिमान और सशक्तीकरण का नया दौर

महतारी वंदन योजना से आत्मनिर्भरता, सम्मान और आर्थिक शक्ति की नई कहानी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

महतारी वंदन योजना: आर्थिक संबल से आत्मविश्वास तक



लगभग

70 लाख

महिलाएं लाभान्वित



अब तक 27 किस्तों में

17,523 करोड़

रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में



महतारी सदन (अब तक)

368 स्वीकृत

137 का निर्माण पूर्ण



- प्रतिमाह 1,000 रुपए की सहायता, सीधे बैंक खाते में
- छोटी बचत, बच्चों की पढ़ाई, खेती और छोटे व्यवसाय में सहायक
- आत्मसम्मान, आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता की नई पहचान
- महिलाओं के जीवन में स्थिरता और समाज में सकारात्मक बदलाव

बजट में भी महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता



800 करोड़

आंगनबाड़ी संचालन हेतु



650 करोड़

पूरक पोषण आहार हेतु



235 करोड़

कुपोषण मुक्ति एवं पोषण अभियान हेतु



8,245 करोड़

महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु



2,320 करोड़

आंगनबाड़ी एवं पोषण योजनाओं हेतु



750 नए

आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु 42 करोड़



250

महतारी सदनों के निर्माण हेतु 75 करोड़

स्वावलंबन से नेतृत्व तक



स्व-सहायता समूहों को रेडी-टू-ईट कार्य से जोड़कर स्थायी आय का अवसर



उज्ज्वला योजना से 38 लाख महिलाओं को स्वच्छ ईंधन की सुविधा



डिजिटल सखी, दीदी ई-रिक्शा, सिलाई मशीन सहायता से नए आजीविका अवसर



प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत 3.73 लाख से अधिक पंजीयन



सखी वन स्टॉप सेंटरों की संख्या 27 से बढ़कर 34, 14,300 से अधिक प्रकरणों में 8,900 का निराकरण

“ महतारी वंदन योजना ने महिलाओं को आत्मसम्मान के साथ जीने की ताकत दी है। ”

महतारी गौरव वर्ष 2026

महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का संकल्प वर्ष

संवाद-48628/1